हिन्दी साप्ताहिक
R.N.I. No. UPHIN/2022/83621

जनता का सच

वर्ष 04 अंक 42 | लखनऊ शनिवार 25 अक्टूबर 2025 | पृष्ठ 04 मूल्य 2 रूपया

पीएम मोदी ने रोजगार मेले में सौंपे 51 हजार नियुक्ति पत्र कहा...

युवाओं का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता

नई दिल्ली ,24 अक्टूबर (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 17वें रोजगार मेले में नवनियुक्त युवाओं को 51 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण भाजपा और एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी। ये खुशी आज देश के 51 हजार से अधिक युवाओं को मिली है। मैं महसूस कर सकता हूं कि सभी के परिवार में कितना आनंद होगा। मैं सभी को और उनके परिवारजनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। नवनियुक्त युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपको सिर्फ सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि आप इसी भावना से काम करेंगे।

ईमानदारी और सुचिता के साथ आप भविष्य के भारत के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के लिए नागरिक देवो भवः' ये मंत्र है। पीएम मोदी ने कहा, सेवाभाव और समर्पण भाव से हर नागरिक के जीवन में हम उपयोगी कैसे हों, ये कभी भूलना नहीं है। पिछले 11 सालों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है। उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। हम अपने युवाओं की शक्ति को देश की सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। इसी विश्वास और आत्मविश्वास के साथ हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कि हमारी विदेश नीति भी भारत के युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। हमारे राजनयिक संबंध और वैश्विक समझौते युवाओं के प्रशिक्षण और रोजगार सृजन पर अधिकाधिक केंद्रित हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अकेले रोजगार मेले के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और ये प्रयास सिर्फ सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है।

इसके तहत साढ़े 3 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार त्योहारों के इस मौसम में जीएसटी बचत उत्सव ने भी नए रंग भर दिए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि भारत ने कई यूरोपीय देशों के साथ निवेश साझेदारी की है, जिससे हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा, हमने निवेश को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स व एमएसएमई को समर्थन देने के लिए ब्राजील, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और कनाडा जैसे देशों के साथ कई समझौते भी किए हैं। ये सहयोग निर्यात को मजबूत करेंगे और भारत के युवाओं के लिए विकास व अवसर के नए रास्ते खोलेंगे।

पीएम मोदी ने नागरिकों से छठ को समर्पित गीत साझा करने का किया आग्रह

नयी दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों से छठ पर्व पर आधारित गीत साझा करने का शुक्रवार को आग्रह किया। दिवाली के छह दिन बाद मनाया जाने वाला छठ पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना को समर्पित है। मोदी ने नागरिकों से छठी मैया को समर्पित गीत साझा करके भक्ति और सांस्कृतिक एकता की भावना से जुड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''प्रकृति और संस्कृति को समर्पित महापर्व छठ आने वाला है। बिहार सहित देशभर में इसकी तैयारियों में श्रद्धालु पूरे भक्ति-भाव से जुट चुके हैं।'' उन्होंने कहा, ''छठी मइया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ाने वाले होते हैं। आपसे आग्रह है कि आप भी छठ पूजा से जुड़े गीत मेरे साथ साझा करें। मैं अगले कुछ दिनों तक इन्हें सभी देशवासियों के साथ साझा करूंगा।''

कुरनूल में चलती बस में लगी आग, 20 की मौत व 13 झुलसे

पीएम ने मृतकों के परिजनों को पीएम राहत कोष से दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने की बात कही

करनूल, 24 अक्टूबर (हि.स.)। आंध्र प्रदेश में कुरनूल के बाहरी इलाके चिन्नाटकुरु में एक चलती बस में आग लगने से एक बाइक सवार सहित 20 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 13 लोग झुलस गए हैं। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शोक जताया और मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने की बात कही है। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटना की जांच के आदेश दिए है। तेलंगाना सरकार ने दुर्घटना में मारे गए अपने राज्य के नागरिकों को पांच-पांच रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। शुक्रवार सुबह 3-30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कुरनूल जिले के चिन्नाटकुरु में उल्लिंडकोंडा चौराहे पर एक बाइक से टकराने के बाद हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही वेमुरी कावेरी ट्रैवल्स की बस में आग लग गई। बस में 40 यात्री सवार होने की बात सामने आई है।आग लगने के बाद 12 यात्री किसी तरह कूद कर अपनी जान बचाने में सफल हो गए।हादसे में बाइकसवार और अन्य 19 बस यात्री आग में जिंदा जल गए। अस्पताल से 13 झुलसे लोगों डिस्चार्ज कर दिया गया है1 हादसे में बस चालक और परिचालक बच गए हैं। कुरनूल बस दुर्घटना की जानकारी मिलने पर विदेश से ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंत्री मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी और अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। उन्होंने मृतकों की पहचान करने और परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करने के आदेश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों में निजी बसों की फिटनेस, सुरक्षा और परमिट जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दुर्घटना का कारण लापरवाही पाई गई तो जम्मिेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दुर्घटना में शामिल निजी बस के पंजीकरण, फिटनेस और परमिट की पूरी रिपोर्ट मांगी है। पुलिस जांच कर रही है। इसी बीच तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल के बाहरी इलाके में हुई बस दुर्घटना के पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवज़े की घोषणा की है। दुर्घटना में मारे गए तेलंगाना के नागरिकों के परिवारों को 5 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। बस अग्नि हादसे की सूचना पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। पीएमओ से जारी एक बयान में कहा गया कि आंध्र प्रदेश के करनूल में हुए भीषण सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री को गहरे सदमे में डाल दिया है। इस दुखद घड़ी में उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला

30 वर्ष बाद बढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्तीय अधिकार

लखनऊ ,24 अक्टूबर (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में पांच गुना तक की वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बदलावों से विभागीय अधिकारियों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। उच स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता घटने से निविदा, अनुबंध गठन एवं कार्यारंभ की प्रक्रिया में गति आएगी। यह सुधार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने में सहायक होगा। शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग की बैठक में यह तथ्य सामने आया कि विभाग के अधिकारियों के वित्तीय अधिकार वर्ष 1995 में निर्धारित किए गए थे। इस बीच निर्माण कार्यों की लागत में पांच गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के अनुसार वर्ष 1995 की तुलना में वर्ष 2025 तक लगभग 5.52 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में वित्तीय अधिकारों का पुनर्निर्धारण आवश्यक है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आए और परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जा सके। अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री को सिविल, विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों के लिए वित्तीय अधिकारों की वर्तमान व्यवस्था की जानकारी दी। विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि सिविल कार्यों के लिए अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों की सीमा अधिकतम पांच गुना तक तथा विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों के लिए कम से कम दो गुना तक बढ़ाई जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार मुख्य अभियंता को अब 2 करोड़ के स्थान पर 10 करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार होगा। अधीक्षण अभियंता को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार दिया जाएगा। अधिशासी अभियंता के वित्तीय अधिकार 40 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ किए जाएंगे। सहायक अभियंता को भी सीमित दायरे में टेंडर स्वीकृति एवं छोटे कार्यों की अनुमति देने के अधिकार बढ़ाए जाएंगे। बता दें कि यह पुनर्निर्धारण तीन दशकों के बाद होने जा रहा है। बैठक में उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उचतर) नियमावली, 1990 में संशोधन के माध्यम से विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग की सेवा संरचना, पदोन्नति व्यवस्था तथा वेतनमान के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि नियमावली में किया जा रहा यह संशोधन विभागीय अभियंताओं की सेवा संरचना को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। संशोधित नियमावली में विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग में पहली बार मुख्य अभियंता (स्तर-एक) का नया पद सम्मिलित किया गया है। इसके साथ मुख्य अभियंता (स्तर-दो) और अधीक्षण अभियंता के पदों की संख्या में वृद्धि की गई है।

नवसृजित पदों को नियमावली में समाहित करते हुए उनके पदोन्नति स्रोत, प्रक्रिया और वेतनमान को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे सेवा संरचना अधिक पारदर्शी और संगठित हो सके। बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्य अभियंता (स्तर-एक) के पद पर पदोन्नति अब मुख्य अभियंता (स्तर-दो) से वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। इसी प्रकार मुख्य अभियंता (स्तर-दो) और अधीक्षण अभियंता के पदों पर भी पदोन्नति की प्रक्रिया को नियमावली में स्पष्ट किया गया है।

सिवान में जंगलराज की वापसी नहीं होने देना है: अमित शाह

अमित शाह ने स्वान में जनसभा को किया संबोधित

पटना, 24 अक्टूबर (हि.स.)। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार ने अब रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभाओं को संबोधित किया, वहीं देंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वान में जनसभा को संबोधित किया। सिवान में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्होंने नामांकन के बाद पहली सभा सिवान में रखने कि इच्छा जताई थी। क्योंकि 20 सालों तक लालू-राबड़ी के शासनकाल में सिवान की भूमि ने जंगलराज को सहा है। शहाबुद्दीन के खौफ, अत्याचार और हत्याओं के दौर को सिवान ने झेला है। यहां की भूमि लहूलुहान हो गई, लेकिन सिवान वालों ने झुकना स्वीकार नहीं किया और लालू-राबड़ी शासन को समाप्त कर दिया। शहाबुद्दीन के दौर में हुई हत्या की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी को एकजुट होना है, क्योंकि एक बार फिर से लालू यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से टिकट देने का काम किया है। आप सभी को शहाबुद्दीन के बेटे को हराना है और सिवान को जंगलराज से बचाना है। उन्होंने कहा कि हम यह चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार और नरेन्द्र मोदी मिलकर बिहार को विकास की पटरी पर दौड़ा रहे हैं। अमित शाह ने सिवान जिले में सरकार के द्वारा सड़क, रेल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और बिजली के लिए पावर ग्रिड निर्माण कार्य का जिक्र करते हुए कहा कि लालू यादव को बताना चाहिए की उन्होंने क्या कार्य किए। लालू यादव केवल अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं, जबकि नीतीश सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, पटना को मेट्रो दिया। जीविका दीदियों और आशाओं के मानदेय में वृद्धि की। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभा के दौरान महागठबंधन के सीटों के बंटवारे में झगड़े पर भी तंज कसा और कहा कि अंत समय तक सीटों का बंटवारा नहीं सुलझा, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार कि जनकल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। उन्होंने सभी से पूछा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? भगवान टेंट में थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी की। गृह मंत्री ने पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर कहा कि कांग्रेस की सरकार में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाया जाता था। लेकिन मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्हें सबक सिखाने का काम किया है। घुसपैठियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि घुसपैठिए देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त हैं। हमारा संकल्प है एक-एक घुसपैठियों को बाहर भगाएंगे। इस दौरान सिवान से उम्मीदवार मंगल पाण्डेय, जीरादेई से उम्मीदवार भीष्म प्रताप कुशवाहा, दुरौंधा से उम्मीदवार कर्णजीत सिंह, बरहड़िया से उम्मीदवार इंद्रदेव सिंह पटेल और हथुआ से उम्मीदवार रामसेवक सिंह आदि उपस्थित थे। साथ ही मंच पर सिवान सांसद विजयलक्ष्मी कुशवाहा, पूर्व सांसद ओमप्रकाश यादव, पूर्व सांसद कविता सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी, पूर्व विधान पार्षद मनोज कुमार सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रो. अभिमन्यु सिंह, नगर परिषद की पूर्व सभापति अनुराधा गुप्ता सहित बड़ी संख्या में राजग के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया नवंबर से, जनवरी तक पूरा होगा कार्य

कोलकाता, 24 अक्टूबर (हि.स.)। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के एक वरिष्ठ सूत्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने गुरुवार को दिल्ली में हुई राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) की बैठक में इस संबंध में संकेत दिया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की, जबकि आयोग के अन्य सदस्य सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी उपस्थित रहे। आगामी वर्ष पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इन पांचों राज्यों के सीईओ के साथ आयोग की फुल बेंच ने अलग-अलग बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। आयोग सूत्रों के अनुसार, इन राज्यों को 'एसआईआर' प्रक्रिया में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी ताकि जनवरी के अंत तक सभी कार्य पूरे किए जा सकें।

छठ पूजा कर लौटने वाले यात्रियों के लिए 6181 स्पेशल ट्रेनें चलायेगा रेलवे

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (हि.स.)। भारतीय रेल छठ पूजा के बाद यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक वापसी यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 28 अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान यात्रियों की वापसी यात्रा को सुगम बनाने के लिए 6181 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिससे लोग अपने कार्यस्थलों पर समय पर लौट सकें। रेलवे के अनुसार बढ़ती मांग को देखते हुए नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े जा रहे हैं। प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया को मौसमरोधी बनाया गया है ताकि यात्रियों को ट्रेनों के प्रस्थान से पहले सुविधाजनक प्रतीक्षा स्थल मिल सके। बिहार के पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, समस्तीपुर, बरौनी आदि तथा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बलिया और बनारस जैसे कुल 30 स्टेशनों पर ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, यात्रियों की सुविधा के लिए ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटर और मोबाइल अनरिजर्व्ड टिकटिंग सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। सुरक्षा और संचालन की सुचारू व्यवस्था के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया है। यात्री सहायता बूथ, सूचना काउंटर, कतार प्रबंधन प्रणाली और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को भी और सशक्त किया गया है।

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग जरूरी : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नयी दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के लिए 'क्लाउड सीडिंग (कृत्रिम वर्षा) बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सर्दी के मौसम में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बृहस्पतिवार को किए गए इस सफल प्रायोगिक परीक्षण के बारे में गुप्ता ने कहा, '''क्लाउड सीडिंग ऐसी चीज है जो पहले कभी नहीं हुई। हम शहर भर में यह परीक्षण करना चाहते हैं, क्योंकि यह वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि यह तकनीक सफल होगी। इसका उपयोग भविष्य में पर्यावरणीय चुनौतियों, खासकर सर्दियों के महीनों में सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए किया जा सकता है।

बस में आग लगने जैसी घटनाओं के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी: खरगे

नयी दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक बस में आग लगने के कारण कई लोगों की मौत पर शुक्रवार को दुख जताया और कहा कि बार-बार होने वाली इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। हैदराबाद जा रही एक निजी बस में शुक्रवार तड़के कुरनूल जिले के चिन्नातेकुर के पास एक दोपहिया वाहन के टकराने के बाद आग लग गई, जिससे इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बाइक सवार भी शामिल है। खरगे ने 'एक्स पर पोस्ट किया, ऽआंध्र प्रदेश के कुरनूल में हैदराबाद-बेंगलुरु राजमार्ग पर एक बस में आग लगने की दुखद घटना हुई, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई। यह अत्यंत दुखद है।

रक्षामंत्री ने लोंगेवाला बॉर्डर पर देखा थार शक्ति सैन्याभ्यास

भारतीय सेना हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तत्पर: राजनाथ सिंह

जोधपुर, 24 अक्टूबर (हि.स.)। भारत-पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लोंगेवाला बॉर्डर पर भारतीय सेना की ओर से आयोजित थार शक्ति सैन्याभ्यास का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने सेना की आधुनिक युद्ध क्षमताओं और रेगिस्तानी इलाकों में लड़ाई की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान वह तनोट माता मंदिर पहुंचे जहां मंदिर परिसर में संरक्षित उन बमों को भी देखा, जो आज भी वहां प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। यहां लगे फोटो को लेकर भी जानकारी ली। इसके बाद वे वॉर मेमोरियल पहुंचे और सैनिकों से मुलाकात भी की। उन्होंने यहां 1971 के युद्ध से जुड़ी जानकारियों को पढ़ा। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने जवानों के साहस, पराक्रम और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर है।

चंपावत में खोला जाएगा कृषि विश्वविद्यालय: धामी

देहरादून, 24 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को टनकपुर में शारदा घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में 20.50 करोड़ की 10 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंतनगर की तर्ज पर चंपावत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने व छीनीगोठ क्षेत्र में बाढ़ राहत एवं सुरक्षा कार्य कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की तर्ज पर चंपावत में एक नया कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय से स्थानीय युवाओं को कृषि एवं संबद्ध विज्ञानों में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के अवसर मिलेंगे। यह कदम क्षेत्र में वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देगा और पर्वतीय कृषि अर्थव्यवस्था को नई पहचान देगा। मुख्यमंत्री ने कहाकि छीनीगोठ एवं आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ राहत एवं सुरक्षा कार्य कराए जाने से पूरा क्षेत्र मानसून में होने वाले क्षति से बच सकेगा और कृषि भूमि व सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा ये दोनों घोषणाएं चंपावत को शिक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, उत्तराखंड को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। आज शिक्षा स्वास्थ्य कृषि उद्यान रोजगार देने एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने हर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। चंपावत जिले में भी विकास को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि चंपावत में विकास को आगे बढ़ते हुए इसे एक आदर्श जिले के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

सम्पादकीय

संस्कृति के बहाने हिजाब की पैरवी

केरल में कोच्चि के एक मिशनरी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की जब हिजाब पहनकर आने लगी तो वहां के अधिकारियों ने कहा कि वह स्कूल यूनिफार्म में ही आए। इस पर विवाद हो गया और केरल के शिक्षा मंत्री वी. सिवनकुट्टी भी इसमें कूद पड़े। उन्होंने स्कूल को आदेश दिया कि लड़की को हिजाब पहनकर आने दिया जाए। उन्होंने एक जांच भी बिठा दी, जिसमें कहा गया कि स्कूल के आचरण से बच्ची को बहुत परेशानी हुई। कुट्टी ने यह भी कहा कि स्कूल का इस तरह का आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के मानकों के खिलाफ है। बाद में स्कूल अधिकारियों ने बच्ची के माता-पिता से बात की, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि राजनीतिक दल एसडीपीआइ विवाद भड़काने में लग गया। उसके सदस्यों ने स्कूल वालों के साथ बदतमीजी की, जिनमें से अधिकांश नन थीं।

हिजाब का मामला केरल हाई कोर्ट भी पहुंचा, जिसने स्कूल को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए। इस सबके बीच बच्ची के माता-पिता ने कहा कि वह अपनी बेटी का दाखिला किसी अन्य स्कूल में कराएंगे। केरल सरकार ने इसमें बच्ची की मदद करने की पेशकश की यानी वह भी लड़की को हिजाब सहित पढ़ने की अनुमति देने के पक्ष में खड़ी हो गई। सवाल यह है कि क्या स्कूल अब मजहबी आदेशों से चलेंगे या अपने कायदे-कानूनों और परंपरा से? सिवनकुट्टी जिस वाम दल के प्रतिनिधि हैं, वह धर्म को नहीं मानता, फिर एकाएक उन्हें धार्मिक अधिकारों की याद कैसे आ गई?

कुछ साल पहले कर्नाटक के एक स्कूल को लेकर भी ऐसा ही विवाद हुआ था। इस विवाद को भी राजनीतिक दलों ने खूब हवा दी थी। बहुत सी महिलाएं, जो न कभी हिजाब पहनती थीं, न बुर्का, बल्कि पश्चिमी वेशभूषा में दिखाई देती थीं, उन्होंने हिजाब का समर्थन किया था। यह देखने योग्य है कि स्त्रीवाद की तमाम परिभाषाएं मजहब देखकर ही तय होती हैं। ईरान में खोमैनी के 1979 में सत्ता में आने के बाद स्त्रियों का हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके लिए सड़कों पर मोरल पुलिस घूमती है। जो स्त्रियां हिजाब पहने नहीं पाई जातीं, उन्हें भारी जुर्माना, कोड़ों और जेल की सजा दी जाती।

इसी सजा के चलते 2022 में वहां म्हासा अमीनी की मौत हो गई थी। तब स्त्रियों में गुस्सा फूट पड़ा था। उन्होंने सिर से हिजाब उतार फेंके थे। वे प्रदर्शन करने लगीं। वहां की सरकार ने इस आंदोलन को निर्ममता से कुचला। बहुत से स्त्री-पुरुष मारे गए। खोमैनी से पहले ईरान में स्त्रियां अपनी पसंद के कपड़े पहनती थीं, लेकिन 1979 की तथाकथित क्रांति ने स्त्रियों को फिर से हिजाब और बुर्के में लपेट दिया।

मामला मजहब और संस्कृति का बताकर चुप्पी साध ली गई। इसके बरक्स तुर्किये में स्त्रियों ने हिजाब के समर्थन में आंदोलन चलाया। वहां स्त्रियां हिजाब पहनने की मांग कर रही थीं। कमाल पाशा ने तुर्की में जो सुधार किए, उनमें स्त्री को पर्दे से बिल्कुल आजाद कर दिया था, लेकिन अब तुर्किये की स्त्रियों को पर्दा चाहिए। कितना विरोधाभास है। शायद इसका कारण सरकारों द्वारा लादे गए कानून होते हैं। उनका विरोध करते-करते कभी-कभी अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार ली जाती है, जैसा कि तुर्किये की स्त्रियां कर रही थीं।

कुछ साल पहले हरियाणा की एक पत्रिका ने घूंघट को स्त्री अस्मिता का प्रतीक बताया था तो काफी विरोध हुआ था, लेकिन इन विरोध करने वालों ने ही हिजाब के मामले में खामोशी ओढ़ ली। आखिर यह कौन सी स्वतंत्रता की चाह है, जो मजहब और संस्कृति का बहाना बनाकर चुप हो जाती है। मेरी पसंद, मेरी आजादी की बात अब यहां तक भी आ पहुंची है कि बात-बात पर पितृसत्ता से मुक्ति की चाहत रखने वाले हिजाब या बुर्के को भी स्त्री अस्मिता का प्रतीक बताने लगे हैं।

चाहे घूंघट हो या हिजाब, इसकी जिम्मेदारी स्त्रियों की ही क्यों है? पुरुषों के लिए ऐसा कोई नियम क्यों नहीं? दुनिया भर में पुरुषों ने तो अपनी ड्रेस पैंट-शर्ट कर रखी है और स्त्रियों के कपड़ों पर चील नजर लगी रहती है। क्या दुनिया के मजहबों और संस्कृतियों को बचाने का ठेका स्त्रियों ने ले रखा है। वे क्या करें, यह लादने वाले आप कौन? क्या इसे दोयम दर्जे की नागरिकता नहीं कहते?

जब राजा राममोहन राय बंगाल में सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, तो वहां एक सती समर्थक गुट भी था। उसने स्त्रियों का एक जुलूस निकाला, जिसमें वे कह रही थीं कि वे सती होना चाहती हैं। 1987 में जब राजस्थान के दिवराला में रूपकंवर सती हो गई थी, तब एक दल की बड़ी महिला नेत्री ने बयान दिया था कि सती होना स्त्री का अपना अधिकार है। आपको शाहबानो केस याद होगा। मामला मात्र गुजारा भत्ते का था।

लोकलुभावन वादों का चुनाव पर क्या असर होगा

66

इन यात्राओं से लग रहा था कि इस बार गठबंधन बड़ी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगा लेकिन ऐन चुनावों के वक्त वो भाजपा से लड़ने की जगह आपस में ही लड़ रहा है।

ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव में विपक्षी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए तेजस्वी यादव बड़े-बड़े वादों पर उतर आए हैं । उनके इन वादों का चुनावों पर क्या असर होगा, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा । सवाल यह है कि क्या सिर्फ इन वादों के भरोसे विपक्षी दल एनडीए को टक्कर दे सकते हैं । प्रथम चरण के मतदान के लिए पन्द्रह दिन भी नहीं बचे हैं लेकिन बिहार में चुनाव की गर्मी नजर नहीं आ रही है. हो सकता है कि छठ पूजा सम्पन्न होने के बाद चुनाव प्रचार में तेजी आए । तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की चुनावी सभाएं शुरू नहीं हो पाई है । ये इसलिए अजीब है क्योंकि चुनाव से दो महीने पहले राहुल गांधी वोट चोर यात्रा निकाल रहे थे । उनकी यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने भी अपनी यात्रा निकाली थी ।

एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर बड़े विवाद हुए हैं लेकिन अंत में वहां सब ठीक नजर आ रहा है । इसके विपरीत गठबंधन में सीट बंटवारे का मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हो पाया है । लगभग 12 सीटों पर गठबंधन के सहयोगियों में दोस्ताना संघर्ष देखने को मिल रहा है । वास्तव में बात सीटों की नहीं है बल्कि गठबंधन की एकता की है जो नजर नहीं आ रही है । देखा जाये तो गठबंधन विमर्श की लड़ाई हार गया है क्योंकि जनता में संदेश चला गया है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है । गठबंधन के लिए जरूरी होता है कि जनता को संदेश जाए कि घटक दलों में कोई विवाद नहीं है और वो पूरी तरह से एकजुट हैं । सरकार गठन के समय घटक दलों में झगड़े होना आम बात है लेकिन चुनाव के समय झगड़े होना सही नहीं है । जनता कैसे विश्वास करे कि अगर गठबंधन सत्ता में आ जाता है तो सभी दल मिलकर सरकार चला सकते हैं । सीटों के बंटवारे पर तो दोनों ही गठबंधनों के घटक दल लड़ रहे थे लेकिन सीट बंटवारे के बाद भी गठबंधन में एकता नहीं है । सवाल यह है कि ऐसे हालात में घटक दल एक दूसरे के लिए चुनाव प्रचार कैसे करेंगे । अगर ऐसा नहीं होता है तो ये दल अपने वोट सहयोगी दलों को कैसे ट्रांसफर करेंगे । वोट ट्रांसफर होना आसान नहीं होता. ये तब हो सकता है, जब सभी दलों में पूरी तरह से एकता हो । जब तक पार्टी का स्थानीय नेतृत्व कोशिश नहीं करता , तब तक वोट ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल होता है।

तेजस्वी यादव इन हालातों से निराश हैं, इसलिए वो लोकलुभावन वादों से चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे हैं । इसकी दूसरी वजह यह है कि नीतीश कुमार 20 साल से लगातार सत्ता में हैं लेकिन उनके खिलाफ सत्ताविरोधी लहर कहीं दिखाई नहीं दे रही है । केंद्र की भाजपा सरकार के 11 साल के शासन के बाद भी कोई सत्ताविरोधी लहर नहीं है । देखा जाए तो सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार ही सत्ताविरोधी लहर होती है । बेरोजगारी, मंहगाई और विकास के मुद्दे पर गठबंधन को ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने वोट चोरी को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी लेकिन राजद ने इस मुद्दे से किनारा कर लिया । ये मुद्दा चुनाव परिणामों के बाद के लिए छोड़ दिया गया है । राहुल गांधी ने इस मुद्दे को शुरू किया था लेकिन अब कांग्रेस ने भी इससे किनारा कर लिया है । एसआईआर के खत्म होने के बाद बिहार की जनता भी संतुष्ट है, इसलिए ये मुद्दा चुनाव में फायदा देने वाला नहीं है। लगता है कि तेजस्वी यादव को अब चुनाव जीतने के लिए सिर्फ लोकलुभावन वादों पर ही भरोसा रह गया है, इसलिए उन्होंने बड़े-बड़े वादे करने शुरू कर दिए हैं । उन्होंने घोषणा की है कि उनकी सरकार बनने के बाद 20 महीने के अंदर हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी । देखा जाए तो ये किसी भी तरह से संभव नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने यह वादा कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये वादा उनके लिए गले की हड्डी बन सकता है क्योंकि इसे पूरा करना बहुत मुश्किल होगा । सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव इस बात को नहीं जानते हैं कि वो ये वादा पूरा नहीं कर सकते । वास्तव में तेजस्वी यादव जानते हैं कि वो ऐसा वादा कर रहे हैं जिसे पूरा करना संभव नहीं है । एक बार किसी तरह से सत्ता मिल जाए, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं । जब सत्ता मिल जाएगी, तो इस वादे का क्या करना है, उस पर भी उन्होंने विचार किया होगा । कांग्रेस ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में हर महिला को एक लाख रुपए वार्षिक देने का वादा किया था, उसे भी पूरा करना संभव नहीं था । इस सच को कांग्रेस भी जानती थी, लेकिन वादा किया और उसका फायदा भी उसे मिला । तेजस्वी यादव ने 22 अक्टूबर को एक बार फिर बिहार की जनता से बड़े वादे कर दिए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि सभी संविदा कर्मियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा जीविका दीदीयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। जीविका दीदीयों को 30000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की है कि जीविका दीदीओं के सभी ऋण माफ किए जाएंगे और उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जब उन्होंने हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था तो यह कयास लगाया जा रहा था कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, इसलिए कुछ लोगों को संविदा पर भर्ती किया जाएगा । अब तो तेजस्वी यादव ने वो संशय भी दूर कर दिया है क्योंकि उन्होंने नया वादा किया है कि सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा । बिहार की जनसंख्या को देखते हुए ऐसी नौकरियों की संख्या 2 करोड़ के करीब बैठती है जबकि बिहार में लगभग 15 लाख सरकारी नौकरियां हैं । अगर सभी संविदा कर्मियों को स्थायी कर दिया जाता है तो नई नौकरियां और भी कम हो जाएंगी। इस तरह देखा जाए तो तेजस्वी यादव के लिए दस लाख नौकरियां देना भी मुश्किल दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि तेजस्वी कोई भी वादा करने को तैयार हैं, चाहे उसे पूरा करना कितना भी मुश्किल हो । वो बिहार को कानून बनाकर एक महीने में विकसित राज्य भी घोषित कर सकते हैं। सवाल यह है कि उन्हें इन वादों से कुछ फायदा भी होगा या नहीं। बहुत लोगों के मन में यह सवाल गूंज रहा है कि इन वादों का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। देखा जाए तो इनका असर पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हर महिला को हर साल एक लाख रुपए देने का वादा किया था। इस वादे का कुछ राज्यों में असर देखने को मिला लेकिन कुछ राज्यों में कोई असर नहीं हुआ। केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली-फ्री पानी का नारा देकर चुनाव जीता था। पंजाब में उन्होंने हर महिला को एक हजार रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था जिसे तीन साल बीतने के बावजूद पूरा नहीं किया गया है लेकिन पंजाब में इसको लेकर जनता में ज्यादा नाराजगी नहीं है।

राजेश कुमार पासी

ऐसे अपराधों को रोकने ...

डॉ. रमेश ठाकुर

डिजिटल अपराध में जकड़े बचपन को मुक्त कराने की चुनौती?

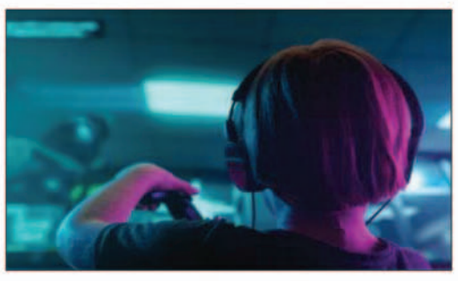

'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' (एनसीआरबी) की हालिया रिपोर्ट ने बच्चों पर बढ़ते अपराधों पर फिर से सोचने पर विवश किया है। पिछली रिपोर्ट के मुताबिक इस बार करीब 10 फीसदी आपराधिक मामलों बढ़ोतरी बताई है। वर्ष-2023-24 में छोटे बच्चों के विरुद्ध देश भर में 1,77,335 आपराधिक मामले दर्ज हुए। ये मामले हिंदी पट्टी वाले क्षेत्रों में ज्यादा रहे जिनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड जैसे राज्य कतार में सबसे उपर हैं। दरअसल, ये मामले सामान्य नहीं, असामान्य हैं? असामान्य का मतलब, ऑनलाइन शोषण और साइबर ग्रूमिंग? इन तकनीकों ने नए सिरे से नए अपराध को जन्म दे डाला है। तस्करों के चंगुल में नौनिहाल ऑनलाइन या ग्रूमिंग के जरिए आसानी से फंस रहे हैं। चाइल्ड क्राइम की इस नई तकनीक को कानून ने 'डिजिटल अपराध' का नाम दिया है। बाल अपराधों में 'डिजिटल खतरों' का बढ़ना निसंदेह चिंताजनक कहा जाएगा। इन बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने को सरकारी तंत्र भी हांफने लगा है। केंद्र सरकार की पहल पर विभिन्न राज्यों में अलग से साइबर थानों को स्थापित करना, डिजिटल क्राइम प्रोटेक्शन विंग का बनाना, पुलिसकर्मियों की अलग से तैनाती के अलावा विदेशी तकनीकों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही। साल-दर-साल चाइल्ड क्राइम घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। इन नाकामियों पर हम सिर्फ शासन-प्रशासन को ही दोषी नहीं ठहरा सकते बल्कि समाज की सामूहिक असफलता भी बड़ा कारण है। ऐसे अपराधों को रोकने में सामाजिक चेतनाएं शांत हैं, अब उनका जगना बेहद जरूरी हो गया है। क्राइम होते देखकर भी लोग मुंह फेर लेते हैं लेकिन, इतना ध्यान रहे, नए जमाने का ये नया अपराध कभी भी, कहीं भी, किसी के चौखट पर दस्तक दे सकता है? इसलिए सबों को मिलकर इस लड़ाई से लड़ना होगा। बाल तस्करी देश के कोने से कोने में हो रही है। वैसे, देखा जाए तो बाल अपराध सर्वाधिक घरों से ज्यादा पनप रहे हैं। मौजूदा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा करती है। चाइल्ड क्राइम में तकरीबन नब्बे फीसदी भागीदारी अपनों की बताई गई है। छोटे बच्चों से जबरदस्ती करना और बलात्कार के मामलों में चाचा, मामा, पापा, पिता या अन्य किसी करीबी का होना ही बताया है। बाल अपराधों को घटित करने में चाहे बाहरी हो या घर का सभी डिजिटल का सहारा लेते हैं। एंड्राइड फोन का लालच देकर बच्चों को फंसाते हैं और उसके बाद अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। एनसीआरबी की मानें तो हैदराबाद, देहरादून, लखनऊ, बरेली व चंडीगढ़ में कुछ ऐसे केस रिपोर्ट हुए हैं, जहां अपनों ने ही अपने बच्चों को फोन में एडल्ट फिल्में दिखाकर उनका शोषण किया। इन हरकतों को देखकर ही लगता है कि बच्चों पर डिजिटल खतरे अब ज्यादा मंडराने लगे हैं। बचाव के लिए बच्चों पर निगरानी ही समाधान का पहला रास्ता है। बच्चे किसी भी क्राइम जैसे हिंसा, शोषण, बलात्कार, अपहरण और यौन अपराधों की भेंट न चढ़ें, उसके लिए हमें चौबीसों घंटे बच्चों के प्रति चौकन्ना रहना होगा। जितना हो सके, बच्चों को फोन मुहैया न करवाएं तो बेहतर होगा। एनसीआरबी के आंकड़े न सिर्फ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं बल्कि शर्म सार भी कर रहे हैं ? पिछले वर्ष दर्ज पॉक्सो मामलों में इस बार एक तिहाई बच्चियों का रेप उनके अपनों ने ही किया। 3569 मामलों में 3,224 में परिवार के सदस्य ही आरोपी रहे। कम उम्र की बच्चियों से उम्रदराज लोगों द्वारा जबरन विवाह करना, अपहरण, मानव तस्करी, जबरन भीख मंगवाना, बच्चों को बेचना, या उनका यौन शोषण करने का सिलसिला तो बदस्तूर जारी है ही । बढ़ते चाइल्ड क्राइम पर केंद्रीय हुकूमत से लेकर पॉक्सो अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट व बाल अधिकार आयोग, निपसिड जैसे विभाग भी चिंतित और रोकने को लेकर प्रयासरत हैं लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल रही जितने की उम्मीदें हैं। बहरहाल, बाल अपराधों को रोकने के समाधान क्या हों? ये ऐसा विषय बन चुका है जिस पर विमर्श लंबे वक्त से जारी है। अब तक के विमर्श से जो निष्कर्ष निकला, उसमें मुकम्मल रूप से दो कारण तेजी से उभरें। अव्वल, एकल परिवार के संस्कारों में तेजी से होता बिखराव, वहीं, दूसरा पारिवारिक एकता के मूल्यों में आयी गिरावट ने इन अपराधों का ज्यादा हौसला बढ़ाया है।

राम युग...

चंद्र मोहन

दीपोत्सव पर पटाखे फोड़ने की परम्परा कब शुरू हुयी ?

दिवाली का उत्सव आते ही पटाखों की चर्चा होने लगती है क्योंकि ये वातावरण प्रदूषण में बहुत वृद्धि कर देते हैं। पीछे कई साल तो सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बेचने पर प्रतिबंध लगाए रखा पर इस साल कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दे दी। फिर क्या था। उंगली पकड़ने की अनुमति मिलते ही पहुंचा पकड़ने वाली जनता ने जम कर हर तरह के पटाखे जलाये जिस से प्रदूषण में भारी वृद्धि हुई। क्या राम जी के अयोध्या आने पर पटाखे फोड़े गए थे ? या क्या यह हिन्दू परम्परा है , आइए जानते हैं।

राम युग में आतिशबाजी नहीं थी; यह दीपावली का हिस्सा नहीं था. दिवाली पर पटाखों की शुरुआत मुगल काल के दौरान हुई जब बारूद का उपयोग उत्सवों में होने लगा। यह परंपरा 18वीं-19वीं सदी तक भारत में आम हो गई और तब से यह त्यौहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई.

राम युग और दिवाली

राम युग में दिवाली को दीपों और रोशनी के साथ मनाया जाता था. जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने उनके स्वागत में दीये जलाए थे, न कि पटाखे फोड़े थे.

पटाखों का आगमन और विकास

प्राचीन कालः पटाखों का आविष्कार सबसे पहले प्राचीन चीन में हुआ था जहां बांस के डंठलों को आग में फेंकने से उनमें से तेज आवाज आती थी और बुरी आत्माएं दूर भागती थीं.

मध्यकाल –

बारूद भारत में 8वीं शताब्दी में पहुंचा लेकिन इसका उपयोग युद्धों तक ही सीमित था. 13वीं शताब्दी के

बाद, बारूद की तकनीक भारत में फैल गई.

मुगल काल –

15वीं शताब्दी में, मुगल काल के दौरान, पटाखों को शाही समारोहों और उत्सवों का हिस्सा बनाया गया.

आधुनिक काल -

18वीं से 19वीं सदी के दौरान दिवाली पर पटाखे जलाना आम हो गया और भारत में पटाखा कारखाने स्थापित होने लगे. शुरुआत में कोलकाता में और बाद में शिवकाशी इसका प्रमुख केंद्र बन गया.

भारत में पटाखों की परंपरा की शुरुआत मध्ययुगीन काल में मानी जाती है. कुछ स्रोतों के अनुसार, 13वीं शताब्दी में पटाखे भारत आए जबकि अन्य 1400 ईस्वी के आसपास चीनी पाइरोटेक्निक फॉर्मूलों के भारत पहुंचने की संभावना जताते हैं. भारत में सबसे पहले पटाखों का इस्तेमाल दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान हुआ.

कई इतिहासकारों का मानना है कि आतिशबाज़ी का विकास मूल रूप से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के प्राचीन लियुयांग में हुआ था। पहले रपटाखेर बाँस के डंठल होते थे जिन्हें आग में डालने पर, बाँस में मौजूद खोखली हवा की थैली के ज़्यादा गरम होने के कारण, ज़ोरदार धमाके के साथ फट जाते थे.

जरा हटके

नए हलफनामे में ...

कुमार कृष्णन

जय सम्राट, जय सम्राट और उलझे सवाल

बिहार के मुंगेर जिले का एक प्रमुख अनुमंडल स्तरीय कस्बा तारापुर इतिहास, संस्कृति, आस्था और राजनीति के कई रंगों को समेटे हुए है। तारापुर विधानसभा क्षेत्र जमुई लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में असरगंज, टेटिहा बम्बर, संग्रामपुर और खड़गपुर ब्लॉक की आठ ग्राम पंचायतें शामिल हैं। 1951 में स्थापित इस क्षेत्र ने 19 बार विधायक चुने हैं, जिनमें दो उपचुनाव शामिल हैं।

इस क्षेत्र की राजनीतिक विशेषता यहां की ओबीसी आबादी, खासकर कुशवाहा समुदाय का प्रभाव है। यहां से चुने गए अधिकांश विधायक इसी जाति से रहे हैं चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसी तारापुर सीट से भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस कारण यह हाट सीट है। तारापुर विधानसभा सीट पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपने गृह क्षेत्र में लगे "जय सम्राट,जय सम्राट" के बैनर देखकर खुश हुए होंगे लेकिन उन्होंने 10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है जिसने उनकी उम्र और शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सम्राट चौधरी की जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यताएं स्पष्ट नहीं हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इन विवरणों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि हलफनामे में चौधरी की 10वीं कक्षा कब पूरी हुई, इसका उल्लेख नहीं है जबकि उन्होंने पहले ऐसी जानकारी देने का दावा किया था।

सम्राट चौधरी ने कामराज विश्वविद्यालय से प्री-फाउंडेशन कोर्स (पीएफसी) पूरा किया है। यह दावा भी चौंकाने वाला

है क्योंकि पीएफसी आमतौर पर तमिल भाषियों के लिए होता है और उनकी 10वीं कक्षा की पढ़ाई का कोई जिक्र नहीं है। उनकी सर्वोच्च योग्यता "मानद" डॉक्टर ऑफ लेटर्स (डीएलआईटी) है जबकि उन्होंने कामराज विश्वविद्यालय से 'पीएफसी' की उपाधि का उल्लेख किया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने ये योग्यताएं कब हासिल कीं।

नए हलफनामे में सम्राट चौधरी द्वारा 2020 के विधान परिषद चुनावों के दौरान घोषित की गई बातों को ही बरकरार रखा गया है। उन्होंने तब घोषणा की थी कि उनकी डी.लिट. की डिग्री 'कैलिफ़ोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी' से है जो एक अमेरिकी संस्थान है और अपनी वेबसाइट के अनुसार मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है। उन्होंने कामराज विश्वविद्यालय से 'पीएफसी' भी सूचीबद्ध किया था। 2020 में भी उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने डी.लिट. की डिग्री कब प्राप्त की या 'पीएफसी' कब किया।

दरअसल, 1999 में जब चौधरी राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली राजद सरकार का हिस्सा थे, तब पार्टी के नेता के तौर पर उन्हें अपनी उम्र को लेकर उठे विवाद के कारण इस्तीफा देना पड़ा था।

चौधरी द्वारा हलफनामा दाखिल करने के तुरंत बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा नेता ने "उम्र को लेकर मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब नहीं दिया है और न ही इस बारे में कि क्या वह 1995 के तारापुर मामले में अभियुक्तों में से एक थे जिसमें छह लोग मारे गए थे।" उन्होंने आगे कहा, "वह इस बात पर भी चुप रहे कि क्या उन्हें नाबालिग होने का प्रमाण पत्र दिखाकर ज़मानत मिली थी जबकि उस समय वह नाबालिग नहीं थे।"

किशोर ने चौधरी पर 1995 के तारापुर में छह लोगों की मौत से जुड़े एक मामले में सुनवाई से बचने का भी आरोप लगाया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने उस समय नाबालिग होने का झूठा प्रमाण पत्र जमा किया था। हलफनामे में चौधरी की उम्र 56 साल बताई गई है जो मतदाता सूची पर आधारित है लेकिन स्कूल का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। इन विवादों के बावजूद, चौधरी का कहना है कि उनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता कामराज विश्वविद्यालय से पीएफसी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने इस बहस को और हवा दी है। वीडियो में चौधरी पत्रकारों को रपीएफसीर का मतलब समझाने में संघर्ष करते दिख रहे हैं जिससे उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल और गहरा गए हैं। प्रशांत किशोर ने इस मामले को लेकर चौधरी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हलफनामे में 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने की तारीख का उल्लेख नहीं है। यह तब है जब चौधरी ने पहले कहा था कि वे इस जानकारी को शामिल करेंगे। सम्राट चौधरी का कहना है कि उन्होंने कामराज विश्वविद्यालय से पीएफसी किया है। यह बात लोगों को हैरान कर रही है क्योंकि पीएफसी कोर्स आमतौर पर तमिल बोलने वालों के लिए होता है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने 10वीं कक्षा कब पास की। प्रशांत किशोर ने यह भी आरोप लगाया है कि चौधरी ने 1995 में तारापुर में हुई छह लोगों की मौत के मामले में सुनवाई से बचने के लिए खुद को नाबालिग बताया था और इसके लिए झूठा प्रमाण पत्र दिया था। हलफनामे में उनकी उम्र 56 साल लिखी है, जो मतदाता सूची के अनुसार है लेकिन स्कूल का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। इन सब बातों के बावजूद चौधरी का कहना है कि उन्होंने कामराज विश्वविद्यालय से पीएफसी किया है जो उनकी सबसे बड़ी शैक्षणिक योग्यता है।

किशोर के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर सम्राट चौधरी के अनुसार , "मैंने कभी डी.लिट. की डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ाई नहीं की। यह मानद है। मैंने यह भी घोषित किया है कि मैंने एक प्री-फाउंडेशन कोर्स (पीएफसी) किया है जिसे कुछ मामलों में दसवीं कक्षा के समकक्ष माना जाता है। जहां तक तारापुर मामले की बात है, मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं है। मैं किसी ऐसी चीज़ पर प्रतिक्रिया क्यों दूँ जो पहले से ही अदालती रिकॉर्ड में दर्ज है? मैं किसी के उकसावे में नहीं आऊँगा और अपने चुनाव अभियान पर ध्यान केंद्रित करूँगा, जो विकास के एजेंडे के इर्द-गिर्द है।"

जिलाधिकारी ने की विकास कार्यों की समीक्षा

योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता हो सर्वोपरि

गोंडा। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के ब्लॉक प्रमुखगण, खंड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय से और बिना किसी भेदभाव के पहुँचे, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए तथा सभी योजनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टियाँ, भौतिक प्रगति रिपोर्ट और वित्तीय उपयोग प्रमाणपत्र समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराए जाएँ। डीएम ने विशेष रूप से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी ब्लॉकों में चल रहे कार्यों का नियमित निरीक्षण किया जाए और शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाए। बैठक में जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दूबे, और परियोजना निदेशक डीआरडीए अजय प्रताप सिंह ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे मिलकर जनपद को मॉडल जिला बनाने की दिशा में कार्य करें ताकि विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ आमजन तक पहुँच सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन, डीसी मनरेगा, डीसी एनआरएलएम जे.एन. राव, जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी, जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह सहित अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मूर्ति विसर्जन से लौट रहे तीन युवकों को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने रौंदा, एक की हालत नाजुक

गोंडा। नवाबगंज थाना क्षेत्र के कटी चौराहे के पास देर रात हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे तीन बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने रौंद दिया। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, सरयू नदी अयोध्या में मां लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन कर वजीरगंज लौट रहे तीनों युवक — पंकज मिश्र (28 वर्ष), पंकज पाल (18 वर्ष) और अजय पाल (20 वर्ष), निवासी ग्राम सिरसा — बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। तभी नवाबगंज क्षेत्र के कटी चौराहे के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल हादसे की सूचना नवाबगंज पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अभय सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों घायलों को सरकारी एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नवाबगंज पहुंचाया। अधीक्षक डॉ. राम मोहन सिंह ने बताया कि पंकज मिश्र के सिर और दाहिने हाथ में गंभीर चोटें हैं, जिसके चलते उन्हें बेहतर इलाज के लिए अयोध्या के दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं, अन्य दोनों घायल — पंकज पाल और अजय पाल — को प्राथमिक उपचार के बाद गोंडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत सामान्य है। इधर, हादसे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है ताकि दुर्घटना करने वाले वाहन की पहचान की जा सके। परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कटी चौराहे पर आए दिन तेज रफ्तार वाहनों की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी समाधान और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। एक लापरवाह रफ्तार ने फिर तीन परिवारों की खुशियाँ छीन लीं — त्योहार की रात मातम में बदल गई।

एक नजर

खैरा भवानी मंदिर में छठ महापर्व की तैयारियां शुरू

गोंडा। ऐतिहासिक खैरा भवानी मंदिर परिसर में छठ महापर्व की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। मंदिर के विशाल पोखर के घाटों पर सफाई अभियान तेज कर दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पोखर में पड़ी मूर्तियों के अवशेष भी हटाए जा रहे हैं। अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने घाटों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल व सुरक्षा इंतजाम को समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। एडीएम ने बताया कि इस ऐतिहासिक पोखर पर हर वर्ष हजारों महिलाएं सूर्योपासना कर छठ व्रत का अनुष्ठान करती हैं। इस दौरान लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। महिलाओं द्वारा अपने-अपने घाट तैयार करने और उन पर नाम अंकित करने की परंपरा इस स्थल की विशेषता है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मोबाइल टॉयलेट, प्रकाश व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति की विशेष तैयारी की जा रही है। वहीं पुलिस विभाग को सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। एडीएम ने स्पष्ट किया कि तैयारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि श्रद्धालु निर्बाध और सुरक्षित वातावरण में छठ पर्व का व्रत पूरा कर सकें।

उम्मीद पोर्टल से सम्बन्धित सेमिनार 25 अक्टूबर को

बहराइच। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मो. खालिद ने बताया कि जनपद बहराइच की समस्त वक्फसंपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर भरे जाने हेतु 25 अक्टूबर 2025 को पूर्वान्ह 11.00 बजे वक्फनं. 19 दरगाह शरीफ बहराइच स्थित बरातघर में सेमिनार आयोजित किया गया है। जिसमें वक्फबोर्ड द्वारा नामित कोआर्डिनेटर एवं मुतवल्ली 20-20 वक्फ मुतवल्लियों के साथ प्राथमिकता करेंगे, ताकि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की फीडिंग का कार्य निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराया जा सके।

नयी पुलिस चौकी के निर्माण हेतु भूमि पूजन संपन्न

कैसरगंज, बहराइच। थाना कैसरगंज क्षेत्र के ग्राम हरनी में शुक्रवार को नयी पुलिस चौकी के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम बड़े ही श्रद्धापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि सुनील सिंह, उपजिलाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह तथा क्षेत्राधिकारी रवि खोखर ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन कर चौकी निर्माण की औपचारिक शुरुआत की। सांसद प्रतिनिधि सुनील सिंह ने इस अवसर पर कहा कि हरनी में पुलिस चौकी की स्थापना से क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। दूरस्थ गांवों तक पुलिस की पहुँच तेज होगी जिससे नागरिकों को समय पर सुरक्षा और सहयोग मिल सकेगा। क्षेत्राधिकारी रवि खोखर ने बताया कि यह पुलिस चौकी अपराध नियंत्रण एवं जनसुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। चौकी क्षेत्र में दस ग्राम पंचायतें शामिल होंगी जिनमें गोंडा जनपद की सीमा से सटा अंतर-जनपदीय बॉर्डर क्षेत्र भी आता है। उन्होंने कहा कि चौकी बनने से त्वरित न्याय और सुरक्षा की भावना जनमानस में और गहरी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि चौकी का निर्माण विभागीय संसाधनों एवं जनसहयोग से कराया जा रहा है। इस अवसर पर थाना प्रभारी निरीक्षक बृजेंद्र कुमार मिश्र, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजन सिंह, चौकी प्रभारी बृजेंद्र गौड़, तथा क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

छोटी थाली में बड़ा बदलाव, पयागपुर की ममता में दिखा मातृत्व पोषण का असर

बहराइच। गर्भावस्था के नौ महीने केवल एक बच्चे के जन्म तक सीमित नहीं हैं बल्कि ये भविष्य की सेहत की बुनियाद रखते हैं। इस दौरान मां को मिले सही पोषण का असर पीढ़ियों तक महसूस किया जा सकता है। विशेषज्ञ चिकित्सक इसके लिए दैनिक भोजन में पौष्टिकता शामिल करते हुए गर्भवती को पूरक आहार के रूप में प्रतिदिन आयरन फोलिक एसिड टेबलेट लेने की सलाह देते हैं। एसीएमओ डॉ. संतोष राना के अनुसार, गर्भावस्था में महिला स्वयं के साथ गर्भस्थ शिशु का भी पोषण करती है। ऐसे में सही पोषण न मिलने पर उसे एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है, इससे प्रसव दौरान या पश्चात रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए गर्भवती को दैनिक भोजन में पौष्टिकता शामिल करने और आयरन फोलिक एसिड व कैल्शियम की टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। सीएमओ डॉ. संजय कुमार के अनुसार, आयरन फोलिक एसिड टेबलेट सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध हैं और इसे ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित वीएचएसएनडी सत्रों के दौरान सभी गर्भवती महिलाओं को एक गोली और एनिमिक गर्भवती को प्रतिदिन दो गोली सेवन के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत भी गर्भवती महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य जांच और सुरक्षित प्रसव सेवाओं की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। एचएमआईएस आंकड़ों के अनुसार जनपद में अप्रैल 2024 से सितंबर 2025 तक कुल 74,542 गर्भवती महिलाओं में से 71,868 महिलाओं को आयरन-फोलिक एसिड टेबलेट दी गई और 5463 गंभीर एनीमिक महिलाओं का आयरन सुक्रोज इंजेक्शन के माध्यम से सफलतापूर्वक इलाज किया गया। इन प्रयासों से न सिर्फ एनीमिया का प्रबंधन किया गया बल्कि 45,323 माताओं का अस्पताल में सुरक्षित प्रसव भी कराया गया। पयागपुर की एएनएम शशी प्रभा कहती हैं पहले गर्भवती और धात्री माताएं पोषण पर बात करने में झिझकती थीं, उन्हें लगता था कि इसमें खर्च अधिक आएगा।

जिला पंचायत अध्यक्ष पर झूठा शपथ पत्र देने का आरोप, जॉच की मांग से मचा सियासी हड़कंप

अम्बेडकरनगर। जिले की राजनीति इन दिनों एक नए विवाद में घिर गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा पर चुनाव के दौरान झूठा शपथ पत्र देने का गंभीर आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता मेराज अहमद ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र भेजकर इस मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।शिकायत के अनुसारए वर्ष 2021 में हुए जिला पंचायत सदस्य चुनाव में श्याम सुंदर वर्मा ने टांडा पूर्वी उत्तरी सीट से प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था कि उनके खिलाफकोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद वे जिला पंचायत अध्यक्ष बने।हालांकिए शिकायतकर्ता का दावा है कि यह जानकारी भ्रामक और असत्य थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में इब्राहिमपुर थाने में श्याम सुंदर वर्मा के खिलाफैब्ब्ेज् एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया थाए जिसकी चार्जशीट 2019 में दाखिल की गई थी।मेराज अहमद ने अपने पत्र में कहा है कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा चुनाव प्रक्रिया में झूठा शपथ पत्र दाखिल करना न केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन हैए बल्कि यह नैतिकता और आचार संहिता के भी विपरीत है। उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाए।सूत्रों के मुताबिकए शिकायत की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारीए पुलिस अधीक्षक और एसडीएम टांडा को भी भेजी गई है। प्रशासन ने शिकायत की जांच कराए जाने की पुष्टि की है।यदि आरोप सही साबित होते हैंए तो यह मामला जिला पंचायत अध्यक्ष के पद और राजनीतिक भविष्य दोनों पर असर डाल सकता है।

एक नजर

राजकीय जिला पुस्तकालय का डीएम ने किया निरीक्षण

बहराइच। आकांक्षात्मक जनपद कार्यक्रम, नीति आयोग, भारत सरकार के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था उ.प्र. लघु उद्योग निगम लि. निमार्ण खण्ड-4, देवीपाटन मण्डल बहराइच को स्वीकृत धनराशि रू. 01 करोड 03 लाख 68 हजार की लागत से गेंद घर मैदान स्थित राजकीय जिला पुस्तकालय भवन की मरम्मत, इन्टरलॉकिंग, आन्तरिक जलापूर्ति एवं विद्युतीकरण, स्कूटर शेड, सोलर स्ट्रीट लाइट, वॉटर कूलर विद आर.ओ., इन्वर्टर, बैट्री, कम्प्यूटर सिस्टम विद प्रिंटर, पुस्तक रखने हेतु अलमारी, कुर्सी, मेज एवं अन्य फर्नीचर का कार्य कराया गया है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी द्वारा राजकीय जिला पुस्तकालय में कराये गये कार्यों का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता चन्द्र प्रकाश त्रिवेदी को निर्देशित किया गया कि पुस्तकालय में एक अन्य भवन व अवशेष इन्टरलॉकिंग कार्य का आगणन तैयार करें। डीएम द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वदा नन्द को निर्देश दिये गये कि पुस्तकालय में आने वाले पाठकों विशेषकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की रूचि एवं आवश्यकतानुसार सूची प्राप्त कर और पुस्तकों की व्यवस्था करायें। साथ ही विद्यार्थियों के लिए आनलाइन टेस्ट सिरीज की व्यवस्था भी करायी जाय। निरीक्षण के दौरान अधि.अधि. नगर पालिका परिषद बहराइच प्रमिता सिंह को निर्देश दिये गये कि पुस्तकालय परिसर की समुचित साफ-सफाई करायी जाय। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मौजूद पाठकों एवं छात्र-छात्राओं से पुस्तकालय के बारे में फीड बैक प्राप्त कर उन्हें उपयोगी टिप्स भी दिये। निरीक्षण के समय मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रद्धा पाण्डेय, अपर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी तीरथ वर्मा व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान

अम्बेडकरनगर। स्थानीय कानून.व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से कस्बा चौकी अकबरपुर की पुलिस टीम ने शुक्रवार को सघन चेकिंग अभियान चलाया। चौकी प्रभारी नेहा सिद्धार्थ के नेतृत्व में हुए इस अभियान में वाहनों के कागजातों की गहन जांच की गई और संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी गई।अभियान के तहत पुलिस टीम ने तहसील तिराहे पर नाकाबंदी कर वाहन चालकों से ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच की। इस दौरान बिना हेलमेट चलने वालों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई।चौकी प्रभारी नेहा सिद्धार्थ ने बताया कि यह अभियान दोस्ताना माहौल में संचालित किया गया ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। हमारा उद्देश्य कानून.व्यवस्था को सुदृढ़ रखना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है। अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभियानों से क्षेत्र में सुरक्षा और अनुशासन का माहौल मजबूत होता है। चौकी प्रभारी ने आगे भी ऐसे अभियानों को नियमित रूप से जारी रखने का आश्वासन दिया।जिला प्रशासन ने भी इस अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने पर पुलिस टीम को बधाई दी है।

पराली जलाने पर होगी सख्त कार्रवाई

अम्बेडकरनगर। उप कृषि निदेशक ने जनपद के सभी किसानों से अपील की है कि वे खेतों में पराली या अन्य कृषि अवशेष न जलाएं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता हैए जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ;एनजीटीद्ध ने इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा है।उप कृषि निदेशक ने बताया कि पराली जलाने की रोकथाम के लिए जनपद तहसील और विकास खंड स्तर पर विशेष टीमें गठित की गई हैं जो लगातार किसानों को जागरूक कर रही हैं। एनजीटी के आदेशानुसार फसल अवशेष जलाना दंडनीय अपराध है और ऐसा करने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क वसूल किया जाएगा।निर्धारित दरों के अनुसार 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर 5000. 2 से 5 एकड़ तक वाले पर 10000 और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में पराली जलाने पर 30000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है।अधिकारी ने बताया कि जनपद में अब तक तहसील अकबरपुर के दो किसानों पर 10000 का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति बार.बार नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफआर्थिक दंड के साथ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।उप कृषि निदेशक ने कहा कि किसानों को पराली जलाने की बजाय इसे गोशालाओं में भेजने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बदले में किसानों को गोबर की खाद उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए ग्राम प्रधानों एफपीओ और अन्य संगठनों के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है।उन्होंने सभी किसानों से अपील की कि वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करें और पराली जलाने से परहेज कर स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण में सहयोग दें। जनपद के विभिन्न ग्रामों ब्लॉकों तहसीलों व चौपालों में इस विषय पर निरंतर जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है।

भीषण सड़क हादसे में एयरबैग की विफलता से गई दो जिंदगियां, उठे गंभीर सवाल

गोंडा। जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र अंतर्गत परसोहिया मोड़ के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। हादसे में मारुति सुजुकी सिलेरियो कार में बैठे नीरज श्रीवास्तव और उनकी चचेरी भाभी आंचल श्रीवास्तव की मौत का कारण केवल टक्कर नहीं, बल्कि कार का एयरबैग समय पर पूरी तरह न खुलना बताया जा रहा है। वहीं, नीरज की पत्नी रोषी श्रीवास्तव इस हादसे में सुरक्षित बच गईं। जानकारी के अनुसार, हादसे के वक्त रोषी श्रीवास्तव ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर बैठी थीं। टक्कर के साथ ही उनके सामने वाला एयरबैग तुरंत और पूरी तरह खुल गया, जिससे उन्हें मामूली भी चोट नहीं आई। इसके विपरीत, ड्राइवर साइड का एयरबैग पूरी तरह नहीं खुल पाया। इसी वजह से नीरज श्रीवास्तव और उनके ठीक पीछे बैठी आंचल श्रीवास्तव की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उस समय सभी यात्रियों ने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। हादसे के बाद कार के एयरबैग की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोगों के बीच यह चर्चा है कि आखिर ड्राइवर साइड वाला एयरबैग क्यों नहीं खुला — क्या यह तकनीकी खराबी थी या फिर कंपनी स्तर पर कोई लापरवाही? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर एयरबैग समय पर खुल जाता, तो शायद दो जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। इस मामले पर ऑटोमोबाइल इंजीनियर ओंकारनाथ तिवारी का कहना है, एयरबैग तभी सक्रिय होता है जब वाहन मानक के अनुरूप चलता है और सिस्टम पूरी तरह सही स्थिति में हो। अगर एयरबैग पूरा नहीं खुला, तो संभव है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक खराबी या कनेक्शन फॉल्ट रहा हो। वाहन मालिकों को सर्विसिंग के दौरान एयरबैग सिस्टम की संपूर्ण जांच अवश्य करानी चाहिए। विशेषज्ञ बताते हैं कि टक्कर लगते ही एयरबैग सेंसर सक्रिय होकर कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजता है। यह यूनिट एयरबैग मॉड्यूल में मौजूद सोडियम एजाइड के जरिए नाइट्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जिससे कुछ ही मिलीसेकंड में एयरबैग फुल जाता है। यदि इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर विलंब या रुकावट आए, तो हादसे की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कंपनियां अपने वाहनों में लगाए जा रहे सुरक्षा उपकरणों की गुणवत्ता को लेकर सचमुच गंभीर हैं? और क्या सर्विस सेंटर एयरबैग जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम की नियमित जांच सुनिश्चित करते हैं?यदि ड्राइवर साइड का एयरबैग समय पर खुल जाता, तो शायद नीरज और आंचल आज ज़िंदा होते।

विद्युत बिल सुधार शिविर में सभी शिकायतों का निस्तारण

अम्बेडकरनगर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर विद्युत बिल संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया गया। आईजीआरएस 1912 हेल्पलाइन व कार्यालय में प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए समस्त अधिशासी अभियंताओं और उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए।इसी क्रम में विद्युत वितरण खंड अकबरपुर के अधिशासी अभियंता ने बताया कि 21 अक्टूबर 2025 को जनपद के चारों खंडों में आयोजित बिल सुधार शिविरों में घरेलू व्यावसायिक और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं से कुल 7 शिकायतें प्राप्त हुईं।

जिले को मिलेंगे दो आधुनिक इनडोर स्टेडियम,खिलाड़ियों को मिलेगा नया उड़ान मंच

राजकीय इंटर कॉलेज और अभिनव इंटर कॉलेज परिसर में होंगे निर्माण, करीब 9.84 करोड़ की लागत से तैयार होंगे अत्याधुनिक खेल केंद्र

(डा0 जी सी श्रीवास्तव)

गोंडा। खेल प्रतिभाओं को निखारने और जिले के खेल ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में गोंडा जल्द ही नई उड़ान भरने वाला है। जिले में दो बहुउद्देशीय इनडोर (मिनी) स्टेडियमों के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। ये स्टेडियम राजकीय इंटर कॉलेज के अदम गोंडवी खेल मैदान और अभिनव इंटर कॉलेज, कंसापुर में बनाए जाएंगे। प्रत्येक स्टेडियम पर 4 करोड़ 92 लाख रुपये की लागत आएगी, यानी दोनों के निर्माण पर कुल 9 करोड़ 84 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जिले के खिलाड़ियों को अब अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इन स्टेडियमों में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग सहित कई इनडोर खेलों की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही शौचालय, चेंजिंग रूम, वार्म-अप जोन, प्रशासनिक कार्यालय, स्वागत कक्ष और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी रहेंगी। खेल सुविधाओं के अलावा इनडोर स्टेडियमों में रनिंग ट्रैक, जिम और मल्टीपरपज फिटनेस हॉल भी बनाए जाएंगे, जिससे खिलाड़ियों का शारीरिक व मानसिक विकास सुनिश्चित हो सके। इन आधुनिक ढांचों से स्थानीय खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। खेल प्रेमियों का मानना है कि यह पहल गोंडा के युवाओं में खेल के प्रति नई ऊर्जा और जोश का संचार करेगी। भविष्य में इन स्टेडियमों में राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन भी संभव होगा, जिससे जिले का नाम खेल मानचित्र पर और चमकेगा। इस बावत जिला खेल अधिकारी ने बताया कि इन इनडोर स्टेडियमों से खिलाड़ियों को न केवल अभ्यास की बेहतरीन सुविधा मिलेगी, बल्कि खेल संस्कृति को भी नया आयाम मिलेगा

गणेश व लक्ष्मी जी की प्रतिमा का हुआ विसर्जन

गिरन्ट बाजार/श्रावस्ती दीपावली पर्व पर धनतेरस के दिन से शुरू हुई पूजा अर्चना माता लक्ष्मी जी व भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना। थाना हरदत्त नगर गिरन्ट क्षेत्र में गिरन्ट हनुमानजी के मंदिर , बडघरपुरवा राम-जानकी मंदिर , जयलालपुरवा में काली माता मंदिर , नव्वापुरवा गांवट समय माता मंदिर , बरगदहनपुरवा बड़े बाबा मंदिर , गडरियनपुरवा गांवट समय माता मंदिर , अयोध्यापुरवा शिव मंदिर , दुर्गापुरवा गांव में शिवजी मंदिर , दुर्गापुरवापूर्वी गांवट माता मंदिर सहित गिरन्ट में नव स्थानों पर पूजा अर्चना शुरू रही चारों तरफ जय लक्ष्मी माता की आरती बजते हुई सुनाई दे रही हैं। गांवों से माताएं बहनें जवान बुर्जुग व युवा आरती में सामिल हो रहे हैं। गिरन्ट क्षेत्र में नव स्थानों पर गुरुवार को भंडारा किया गया। मंडल अध्यक्ष रमेश कुमार उर्फ मंटू यादव ने बताया कि शुक्रवार को बडे ही धूमधाम से शोभायात्रा निकाली। गयी और चौबेडीह गांव के समीप भकला नदी पुल पर जमुनही घाट पर गणेश लक्ष्मी प्रतिमा को ले जाकर विसर्जन किया गया जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जुलूस को गिरन्ट बाजार से गाजे बाजे के साथ ले जाकर जमुनही घाट पर संपन्न हुआ।

जल मिशन योजना बदहाल

गिरन्ट बाजार/श्रावस्ती। जमुनहा विकासखंड मुख्यालय के बगल में बनी पानी टंकी से ग्रामीणों को स्वच्छ पेय जल मिल रहा था जो कई दिनों मोटर खराब हो गया है जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। जिससे लोगों को छोटे नल से मजबूरन इस समय पानी पीना पड़ रहा है जबकि सरकार द्वारा जल मिशन योजना के अंतर्गत टंकी का निर्माण करके स्वच्छ पानी सप्लाई जनता केघ्ए लिए बनवाया था कई लाखों रुपए लगाकर टंकी का निर्माण कराया गया लेकिन जल मिशन कर्मचारियों के लापरवाही से टंकी से मिलने वाला जल ग्रामीण तक नहीं पहुंच रहा है इस संबंध में लोगों ने उपजिलाधिकारी जमुनहा से टंकी को सही करवाने की मांग की हैं।

बाइक सवार बुजुर्ग महिला व युवक कार से टकराकर घायल

महराजगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र में रात में ड्रोन दिखाई देने की खबरों के बीच शुक्रवार की दोपहर महराजगंज रायबरेली मार्ग पर उड़ता ड्रोन कार के सामने आ गया, कार के सामने अचानक ड्रोन के आते ही कार चालक ने ब्रेक लगा दी जिससे कार के पीछे आ रहे बाइक सवार बुजुर्ग महिला व युवक कार से टकराकर घायल हो गये। मौके पर पहुंचे थुलवांसा चौकी प्रभारी ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया व ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना कोतवाली क्षेत्र के महराजगंज रायबरेली मार्ग पर थुलवांसा चौकी क्षेत्र के सोथी गांव के पास की है।

'घरेलू हिंसा/दहेज उन्मूलन' थीम पर जागरूकता चौपाल का आयोजन

रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशानुसार मिशन शक्ति 5.0 के तहत घरेलू हिंसाध्दहेज उन्नमूलन थीम पर ब्लॉक-हरचंदपुर के ग्राम-कठवारा में जागरूकता चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें महिला कल्याण विभाग की यूनिट हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन से शेफाली सिंह जिला मिशन कोऑर्डिनेटर जेन्डर द्वारा घरेलू हिंसा 2005, दहेज उन्नमूलन विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि यदि महिलाओं पर घरेलू हिंसा होती है तो पीड़ित महिला 60 दिनों के भीतर तत्काल दीवानी उपचार प्राप्त कर सकती है। पीड़ित महिलाएँ इस अधिनियम के तहत किसी भी वयस्क पुरुष अपराधी के विरुद्ध मामला दर्ज करा सकती हैं, जो उसके साथ घरेलू संबंध में है यहां तक कि वे महिलाएं जो बहनें, विधवाएं, माताएं, एकल महिलाएं हैं या दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रह रही हैं, प्रस्तावित कानून के तहत कानूनी संरक्षण की हकदार हैं। साथ ही बताया गया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार, विवाह के संबंध में दुल्हन या दूल्हे या उनके रिश्तेदारों से सीधे या परोक्ष रूप से दहेज मांगना एक दंडनीय अपराध है। इस अपराध के लिए छह महीने से लेकर दो साल तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए शिक्षा और जागरूकता फैलाना, कड़े कानून बनाना और उन्हें सख्ती से लागू करना, बेटियों को सशक्त बनाना, और सामाजिक मानसिकता को बदलना आवश्यक है। इसमें बेटियों को अच्छी शिक्षा और करियर के अवसर देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, और विवाह को एक व्यावसायिक सौदा मानने के बजाय आपसी सम्मान और प्यार का रिश्ता मानना है। जेंडर स्पेशलिस्ट पूजा तिवारी द्वारा शासन से संचालित विभागीय योजनाओं जैसे-मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, स्पॉन्सरशिप योजना पर विस्तृत जानकारी देते हुऐ वन स्टापसेंटर के बारे में व टोल फ्री नंबर के बारे में जागरूक किया गया।

अधिकारों को लेकर महापौर और नगर आयुक्त में टकराव

विवाद के चलते बैठक हुई बेनतीजा, प्रस्तावों पर नहीं हुई चर्चा

लखनऊ, । महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव के मध्य बीते काफी समय से चली आ रही तनातनी आखिरकार शुक्रवार को कार्यकारिणी बैठक के दौरान खुल कर सामने आ गयी । शुक्रवार को दोनो के मध्य जमकर वाद-विवाद हुआ । नगर आयुक्त ने महापौर के आदेशो को बिना पढ़े निर्णय लेने से मना कर दिया,कहा नगर निगम के कार्य के लिए नगर आयुक्त के पास नगर निगम अधिनियम के तहत समस्त अधिकार निहित है । ऐसे में किसी भी प्रस्ताव पर बिना पढ़े निर्णय लेना उचित नही होगा । तो वही महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा की कार्यकारिणी अध्यक्ष होने के नाते

दस साल पहले हुआ था निर्णय,अभी तक नही लगी प्रतिमा

कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि 10 साल पहले पूर्व महापौर डॉ दिनेश शर्मा ने पद्म विभूषण अमृतलाल नागर की प्रतिमा लगाने को लेकर चौक चौराहे पर प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने के लिए मौजूदा कार्यकारिणी ने मुहर भी लगा दी थी। इसके बाद भी इतने वर्ष बीतने के बाद भी नगर निगम ने चौराहे पर एक पट्टिका तक लगाने की जहमत नहीं उठाई। कार्यकारिणी सदस्य अनुराग मिश्रा अन्नू ने आरोप लगाया कि कार्यकारिणी के पूर्व अध्यक्षों के फैसलों पर नगर निगम के अफसर निर्णय नहीं ले रहे हैं तो यह किसकी सुनेंगे।

उक्त अधिकार उनके पास निहित है । जिसके पश्चात दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर आमने-सामने आ गए। इस दौरान महापौर ने नगर आयुक्त समेत नगर निगम के जिस अधिकारी से सवाल करती उसके आधे-अधूरे व उलटे जवाब आने पर कार्यकारिणी बैठक गर्मा गयी । जिससे नाराज महापौर सुषमा खर्कवाल दो बार बैठक की कार्यवायी छोड़कर चल दी ,लेकिन अन्य सदस्यो के रोकने व मानमनौव्वल के पश्चात दोबारा बैठी। जिसके पश्चात महापौर ने नये प्रस्तावों पर चर्चा करने से सीधे तौर पर मना कर दिया । नाराज महापौर ने दो माह पूर्व हुई कार्यकारिणी की बैठक में लिए गये निर्णयों के मिनट्स दिखाने के लिए कहा ,उन्होने पूछा की अबतक किस पर क्या कारवाई हुई है।

,जिस पर नगर आयुक्त ने जवाब दिया कि अभी कई प्रस्ताव पर कार्ययोजना तैयार हो रही हैं। इसके बाद महापौर ने नगर निगम में मार्ग प्रकाश व्यवस्था की निविदा से लेकर विधि

अधिवक्ता को लाखों रुपए का भुगतान करने का आरोप

महापौर ने अपर नगर आयुक्त नम्रता सिंह से जवाब मांगा कि जब नगर निगम में 200 वकीलों के पैनल वाली फौज है तो एक विशेष वकीलों को लाखों रुपये का अतिरिक्त भुगतान क्यों किया गया। महापौर ने आरोप लगाया कि अफसरों की मिलीभगत से वकील नमित शर्मा को नगर निगम 5 लाख रुपये से ज्यादा की रकम भुगतान कर चुका है। जबकि नगर निगम में कोई भी वकील अपर पैनल्ड है तो उसे फीस के तौर पर 5400 रुपये का भुगतान किया जाता है। महापौर ने सवाल उठाया कि वकील नमित शर्मा को हटाकर विशेष सचिव लैरिक चौहान को नगर निगम के पैनल्ड में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद भी कार्यकारिणी के इस निर्णय पर कोई फैसला नहीं हुआ। इन सभी सवालों के जवाब नगर निगम के अफसरों के पास नहीं था।

विभाग में अधिवक्ताओं को बेवजह भुगतान किए जाने को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही नगर आयुक्त से पूछा कि कई ऐसे निर्णय भी लिए गए हैं जो नगर निगम के हक में नहीं थे। यह सभी निर्णय कैसे लिए गए। इस पर नगर आयुक्त ने नगर निगम नियमावली 1959 के तहत अपने अधिकारों के तहत सभी निर्णय लिए जाने की जानकारी दी। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अधिनियम के तहत सभी धाराओं का उल्लेख कर अपने कार्यक्षेत्र की जानकारी दी। इससे नाराज महापौर सुषमा खर्कवाल एक बार बैठक से उठकर बाहर जाने लगीं । नाराज महापौर ने समस्त अपर नगर आयुक्तों द्वारा लिए गये गलत निर्णयों को भी लेकर कार्यकारिणी में जवाब मांगा ,जिस महापौर का आरोप है की किसी ने भी संतोषजनक जबाव नहीं दिया है । कहा नगर निगम के अधिकारी लापरवाह हो गये है । करीब चार घंटे तक चली कार्यकारिणी की बैठक में कोई नया फैसला नहीं हो पाया। जिसके चलते शुक्रवार को कई महत्तवपूर्ण बिन्दुओ पर चर्चा कर निर्णय लेने के लिए बुलायी गयी कार्यकारिणी की बैठक पूरी तरह महापौर और नगर आयुक्त के मध्य हुए विवाद की भेंट चढ़ गई।

वर्ष 2022 से गृहकर निर्धारण करने का दिया आदेश

महापौर ने नगर निगम अधिकारियों पर आरोप लगा सवाल उठाया कि भवन स्वामियों को परेशान करने के लिए उनका गृहकर रिवाइज कर साल 2014 से भेजा जा रहा है। जबकि पिछली कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया था कि अब किसी के भवन का गृहकर रिवीजन साल 2022 से किए जाएगा। आरोप है कि जोन स्तर पर धन उगाही के लिए भवनों स्वामियों को बीते कई वर्षों का टैक्स रिवाइज करके भेजा जा रहा है। महापौर ने इसे पूरी तरह गलत बताया और तत्काल टैक्स विभाग को इसमें बदलाव करने का निर्देश दिया। हालांकि टैक्स से जुड़े अफसरों ने इस निर्णय को नगर आयुक्त के ऊपर छोड़ दिया है।

मार्ग प्रकाश की निविदा में घोटाले का आरोप

महापौर ने बैठक में स्ट्रीट लाइटों के लिए हुए टेंडर पर भी सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि बगैर उनकी सूचना के लाइटिंग के लिए पीएमसी गठित कर दी गई है। पीएमसी का हेड राजीव गिरधर को बनाया गया है। जब इतने छोटे टेंडर में पीएमसी गठित हो सकती है तो कुड़े को लेकर पीएमसी गठित क्यों नहीं की गई। महापौर ने सवाल उठाया कि लाइटिंग के छह करोड़ के टेंडर में हैसियत नामा 50 लाख रुपये की रकम तय की गई। जबकि 70 लाख के टेंडर में भी इतनी ही हैसियत नामा रखा गया।

वेतन विसंगति को लेकर भी जताई नाराजगी

नाराज महापौर ने नगर आयुक्त गौरव कुमार से जवाब मांगा कि जब ऑपरेटर स्तर पर सैलरी विसंगति को खत्म करने का निर्णय पिछली कार्यकारिणी में लिया गया था तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। नाराजा जताते हुए कहा कि नगर निगम के अफसरों को अगर कार्यकारिणी के किसी फैसले का पालन नहीं करना है तो आगे से किसी बैठक का कोई मतलब नहीं रह जाता है। महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके मिनट्स अभी तक अफसर जारी नहीं कर पाए हैं। इससे विकास कार्य भी पूरी तरह प्रभावित हो रहा है।

नगर आयुक्त ने भी गिनाए अपने अधिकार

कार्यकारिणी बैठक के दौरान महापौर और नगर आयुक्त के मध्य विवाद गहराने पर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बैठक में ही नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत अपने कार्यक्षेत्र को ही गिनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी का काम एजेंडा होता है, जबकि प्रशासनिक निर्णय लेना उनका काम है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दे हैं जो प्रशासनिक निर्णय पर है इसलिए लिए जाते हैं जो नगर निगम व शहर के हित में होते हैं। ऐसे में प्रशासनिक निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा किए किसे जोनल अफसर बनाना है या किसे टीएस बनाना है यह नगर आयुक्त के अधिकारों में आता है। इस पर कार्यकारिणी कोई फैसला नहीं ले सकती है।

निजी अस्पताल में बच्ची को वेंटिलेटर से हटाया, हालत बिगड़ी

लापरवाही का आरोप लगा परिजनों ने किया हंगामा, सीएमओ से शिकायत

लखनऊ। दुबग्गा के निजी अस्पताल में भर्ती दो साल की मासूम को कर्मचारियों ने वेंटिलेटर से हटा दिया, जिससे बच्ची की हालत हालत बिगड़ गयी। इससे नाराज परिजनों ने इलाज में लापरवाही और रुपये वसूली का आरोप लगाकर हंगामा काटा। जिसके बाद कर्मचारियों ने फिर से बच्ची को वेंटिलेटर पर रख लिया। इस सम्बन्ध में बच्ची के परिजनों ने सीएमओ से शिकायत की है। जिसमें परिजनों ने कहा है कि निजी एंबुलेंस के दलाल उन लोगों को इस निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे और सस्ता व बेहतर इलाज का झांसा देकर भर्ती करा दिया। जानकारी के अनुसार जनपद हरदोई के बघौली स्थित महमूदपुर गांव निवासी संजीत अवस्थी की दो वर्षीय बेटी काव्या को कई दिन से बुखार आ रहा है। परिजन पहले बच्ची को इलाज लिये हरदोई के सरकारी अस्पताल पहुंचे। जहां से बच्ची को लखनऊ के हायर सेंटर के लिए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। निजी एंबुलेंस के दलाल ने सस्ता और अच्छा इलाज मिलने का झांसा देते हुए बच्ची को पहले दुबग्गा स्थित निजी हॉस्पिटल में 20 अक्टूबर को भर्ती कराया, जहां बच्ची की हालत नाजुक देख संचालक ने इसी क्षेत्र के एक बच्चों के अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि इस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के नाम पर रोजाना 15 हजार रुपये वसूले। अस्पताल में इलाज के लिए कोई भी कुशल डॉक्टर मौजूद नहीं था। गुरुवार रात में एक अन्य बच्चे को वेंटिलेटर पर भर्ती कर लिया।

आरोप है कि उनकी बेटी को वेंटिलेटर से हटा दिया। कुछ देर में ही उनकी बेटी की हालत बिगड़ गई। बच्ची को ब्लीडिंग शुरू हो गई। परिवारीजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए शुक्रवार सुबह अस्पताल परिसर में हंगामा किया। इस सम्बन्ध में अस्पताल संचालक का कहना है कि तबीयत में सुधार होते देख बच्ची को वेंटिलेटर से हटाया गया था। वसूली की कोई बात ही नहीं है। पहले ही परिवारीजनों को वेंटिलेटर का चार्ज बता दिया गया था। वही सीएमओ डॉ.एनबी सिंह बताया कि इस मामले की शिकायत मिली है। जांच के लिए टीम गठित करने के निर्देश दिये गये हैं।

डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में आयी कमी-सीएमओ

लखनऊ। डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में पिछले साल की तुलना में इस साल अब तक काफी कमी देखी गयी है। सीएमओ डॉ.एन.बी. सिंह ने बताया कि जन जागरूकता और प्रभावी सर्विलांस और विभिन्न विभागों के समन्वय से ऐसा हो सका है। जिला मलेरिया अधिकारी एवं नगर मलेरिया इकाई की टीम ने इस साल जनवरी से अब तक 18.36 लाख घरों का सर्वे किया। जिसमें 2833 घरों में डेंगू का लार्वा मिला। इसके अलावा 3.62 लाख कंटेनरों के सर्वे में 3.262 में लार्वा पाया गया। कुल 360 घरों को नोटिस भी दिया गया। 2024 में डेंगू के कुल 3215 मामले सामने आये थे, जिसमें जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक 1817 मामले दर्ज किये गये थे। वहीं इस साल जनवरी से अब तक कुल 568 डेंगू के मामले सामने आये हैं। वर्ष 2024 में चिकनगुनिया के कुल 112 मामले थे, जिसमें जनवरी से अक्टूबर 2024 तक 95 मामले थे, जबकि इस साल जनवरी से अब तक कुल 46 मामले आये हैं। यह पिछले साल की तुलना में काफी कम हैं।

तीसरी मंजिल से गिरकर युवक की मौत

लखनऊ। राजधानी के सआदतगंज इलाके में शुक्रवार सुबह एक शख्स की तीसरे मंजिल से गिरकर मौत हो गई। शख्स की पहचान अनिल वर्मा (39) के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक, सुबह के समय अनिल अपने घर की बालकनी से पौधों पर पानी डाल रहे थे। उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर पड़े। परिजन और आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सुबह करीब 7:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। अनिल वर्मा इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे। उनके साले सौरभ ने बताया कि हादसे के समय घर के सभी सदस्य मौजूद थे। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अनिल के परिवार में पत्नी शिल्पी वर्मा हैं, जो क्वीन मैरी अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हैं। उनके दो बच्चे हैं। 12 साल की बेटी अशी और 4 साल का बेटा सुभाष। अनिल के पिता, राधेश्याम वर्मा, जाने-माने नेत्र सर्जन थे जिनका निधन वर्ष 2022 में हो गया था। परिवार पहले से ही पिता के निधन के दुख से उबर नहीं पाया था कि अब अनिल की आकस्मिक मौत ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया है। घटना के बाद से घर में कोहराम मचा हुआ है और परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

राजधानी के चार एसीपी बदले गये

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में तैनात चार एसीपी के कार्य क्षेत्रों में पुलिस कमिश्नर नें फेरबदल किया है। यह फेरबदल क़ानून व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से किया गया है। पुलिस कमिश्नर नें नवरत्न गौतम को एसीपी यातायात बनाया है। वही सतीश कुमार राय को यातायात की जिम्मेदारी दी गई है।विकास कुमार पांडे को एसीपी मोहनलालगंज बनाया गया है। वही रजनीश वर्मा को एसीपी कृष्णा नगर बनाया गया है।

विभूति खण्ड में इण्टर की छात्रा से होटल में रेप

गंभीर धाराओं में केस दर्ज, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

लखनऊ। इंटर की छात्रा के साथ 32 साल के युवक ने रेप किया। युवक ने उससे इंस्टाग्राम से दोस्ती शुरू की। उसके कुछ दिन बाद गोमतीनगर के एक होटल में मिलने के बहाने बुलाया। यहां उसने छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया। लड़की के पिता उसे ढूंढते हुए पहुंच गए थे जिन्होंने रेप करने वाले युवक को मौके पर ही पकड़ लिया। किशोरी जब होश में आई तो परिजन उसे लेकर विभूतिखंड थाने पहुंचे जहां शिकायत दर्ज कराई। किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।आरोपी युवक की पहचान इंदिरानगर सेक्टर-10 के तौकीर आलम के रूप में हुई है। वह विवाहित है और एक बच्ची का पिता भी है।

किशोरी और युवक की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। दोस्ती का हवाला देकर युवक ने बुधवार 22 अक्टूबर को किशोरी को विभूतिखंड स्थित डीएलएफ माई पैड में मिलने बुलाया। यहां उसने कुछ नशीला पदार्थ पिला दिया जिससे किशोरी बेहोश हो गई। इसी बीच तौकीर ने उसके साथ रेप किया। तौकीर शेयर मार्केट का काम करता है।

वह घटना वाले दिन किशोरी को पहले गोमतीनगर स्थित एक क्लब में लेकर गया था। वहां दोनों ने पार्टी की। उसके बाद रात करीब 1 बजे डीएलएफ माय पैड होटल में कमरा बुक किया। वहां उसने किशोरी के साथ रेप किया। किशोरी सुबह अपने पिता से कहासुनी के बाद घर से निकल गई थी। उसके बाद पिता ने किशोरी की लोकेशन की ट्रेस करनी शुरू की। पहले पिता क्लब पहुंचा पर तब तक दोनों लोग होटल पहुंच चुके थे। इसके बाद पिता होटल पहुंचे। वहां उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। उनकी बेटी बेहोश पड़ी थी। इसके बाद पिता ने ही 112 पर कॉल कर घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी युवक को थाने ले आई। किशोरी की हालत खराब थी। होश आने पर उसने पूरी घटना बताई। किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि आरोपी पर रेप और पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। जल्द ही पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा।

महापौर को गुमराह कर रहे नगर निगम अधिकारी

लखनऊ, । नवरात्रि महोत्सव के लिए बीते सितम्बर माह में नगर निगम अधिकारियो की हीलाहवाली के चलते झूलेलाल वाटिका के आवंटन में हुई देरी प्रकरण में शरु हुई जांच में नगर निगम अधिकारी अब एक दूसरे को बचाने में लग गये है । अपर नगर आयुक्त एन की अफसरशाही के चलते हुई देरी के पश्चात झूलेलाल वाटिका का आंवटन न होने के प्रकरण में नगर निगम केअधिकारी अब महापौर सुषमा खर्कवाल को ही गुमराह कर रहे है । सम्पूर्ण मामले में आरोप है की आंवटन पत्रावली तीन सप्ताह तक अपर नगर आयुक्त एन के कक्ष मे ही इधर से उधर टहलती रही । लेकिन सम्पत्ति प्रभारी एसडीएम रामेश्वर सिंह अब महापौर सुषमा खर्कवाल को झूठी रिपोर्ट पेश करने के साथ ही सम्पूर्ण मामले में तहसीलदार अरविन्द पाडेण्य को बली का बकरा बनाने की तैयारी कर रहे है । इसी के चलते बीते सप्ताह एसडीएम द्वारा तहसीलदार को पत्र जारी कर देरी का कारण पूछा गया है । जबकि दूसरी ओर पत्रावली का निरीक्षण करने पर साफ जाहिर हो रहा है की अपर नगर आयुक्त एन द्वारा पहले अन्तिम स्वीकृति दे जंहा पत्रावली को अनुमादित कर दिया गया था। लेकिन चौबीस घण्टे के भीतर ही पत्रावली में हुए हस्ताक्षर को स्वंय ही काट दिया गया था। जानकार बताते है कि झूलेलाल वाटिका के आंवटन को लेकर निजी संस्था रेनबो सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियो से बड़े सुविधा शुल्क की मांग की गयी थी। सुविधा शुल्क न दिए जाने के चलते निजी संस्था को आयोजन के लिए समय पर आंवटन नही किया गया । अब सम्पूर्ण मामला खुलने के पश्चात से नगर निगम प्रशासन के मध्य हड़कम्प मचा हुआ है ।

मायावती ने खत्म की मंडलीय व्यवस्था लागू किया नया जोनल सिस्टम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए मंडलीय व्यवस्था को खत्म कर जोनल व्यवस्था लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रदेश को कुल नौ जोन में बांटा गया है। हर दो मंडल को मिलाकर एक जोन बनाया गया है और प्रत्येक जोन में दो-दो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं एक मुख्य प्रभारी और एक सहायक प्रभारी। बसपा की इस नई संगठनात्मक संरचना का उद्देश्य पार्टी के कार्यों को अधिक सशक्त और क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी बनाना है। मायावती के निर्देश पर जारी नई सूची के अनुसार, घनश्याम चंद्र खरवार को गोरखपुर, अयोध्या और लखनऊ जोन का मुख्य प्रभारी बनाया गया है। गया चरण दिनकर को प्रयागराज जोन का मुख्य प्रभारी तथा विजय प्रताप को सहायक प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को मिर्जापुर जोन का मुख्य प्रभारी और गुड्डू राम को सहायक प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।

दिन रात जारी है राजधानी में अवैध शराब का गोरख धंधा

आबकारी निरीक्षक की कृपा से फल फूल रहा कारोबार, डीओ पूरी तरीके से उदासीन

लखनऊ। राजधानी के कई इलाकों में अवैध रूप से जहाँ देशी शराब का गोरखधंधा दिन रात जारी है।वही खुले आम विक्रेता देशी और अंग्रेजी शराब में मिलावट का खेल कर रहे है। वही कई जगहों पर तो आबकारी निरीक्षकों से मिली भगत कर गुप्त दरवाजे से शराब बेच रहे हैं।यही नही बिक्रेता कई तरह के नियमों की अनदेखी कर रहे है। लेकिन जिला आबकारी अधिकारी को इसकी कोई फ़िक्र नही है। यदि कोई इस मामले की शिकायत भी करता है तो अफसरों की फटकार से बचने के लिए जिले के अफसर यह कहकर बच रहे है कि शिकायत करने वाला व्यक्ति दारू मांग रहा है।

नही दिया तो शिकायत कर रहा है।बताते है कि लखनऊ के सरोजनीनगर और बंथरा तथा मोहनलालगंज और निगोहा तथा नगराम व गोसाई गंज के करीब दो दर्जन से अधिक गावों में अवैध शराब का तेजी से निर्माण हो रहा है।सई नदी के किनारे के गावों में शाम होते शराब बिकनी शुरू हो जाती है। यही नही कई जगहों पर दिन में भी अवैध शराब बेचीं जाती है। सूत्र बताते है कि इन शराब के अवैध अड्डों से इंस्पेक्टर और उनके करिंदे मोटी रकम वसूलते है। जिसके चलते अवैध शराब का निर्माण बंद नहीं हो पा रहा है। शराब की दुकानों में नियमों के बिपरीत शीशी को खोल कर भी शराब की बिक्री की जा रही है। यही नहीं जानकार बताते है कि एक पौवे को खोलकर दो ग्राहकों को आधा-आधा देकर दस से बीस रुपए अतिरिक्त कमाए जा रहे हैं।यही नही कई जगहों पर तो दुकान बन्द होते ही बैकडोर से शराब देने पर अतिरिक्त रूपया वसूला जा रहा है।जबकि आबकारी विभाग ने सुबह 10 से शाम 10 बजे तक दुकान से विक्री करने का आदेश जारी किया है, लेकिन आवंटी व सेल्समैन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे।कुछ जगहों पर तो अतिरिक्त कमाई के चक्कर में चौबीस घंटे शराब बेची जा रही है। क्षेत्रीय लोगों की माने तो इस खेल में इलाकाई आबकारी निरीक्षक खुलेआम संरक्षण देते है। बिना उनकी सहमती के कुछ नहीं हो सकता।ज्ञात हो कि जिले के निगोहा, सिसेंडी, दयालपुर, राती, बेनीगंज, भजा खेड़ा, इंद्रजीत खेड़ा, जौखंडी, सिरौना, हरदोईया, सिठौली, घुसकर, करोरा, नरैना खेड़ा, भट्ठी खेड़ा, कनकहा आदि गावों में धड़ल्ले से अवैध शराब का निर्माण हो रहा है। यू तो आबकारी आयुक्त नें कहने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिये है। लेकिन आबकारी निरीक्षकों को क्षेत्र में जाकर चेकिंग करने की फुर्सत नही है। वह केवल डीओ और डिप्टी की हां हजूरी से आगे नही बढ़ पा रहे है। जानकारों की माने तो यहाँ दर्जनों शराब की दुकानो में रात 10 बजे के बाद सेल्समैन दुकानों का शटर उठाकर 100 से 120 प्रति पौवा की दर से बेच रहे हैं तो कहीं-कहीं दुकानदार अगल-बगल में लगी दुकानों पर शराब की बिक्री करते है। कई जगहों पर तो सेल्स मैन शराब की दुकान के बगल में अलग से दुकान ले रखी है।जिसमें शराब की पेटी रख कर बेचते है। यह दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब बेचते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा उनको भी दे देते हैं। वहीं आबकारी विभाग के लापरवाह रवैया के चलते इन देसी शराब की दुकानो पर सुबह से ही खुल जाती है और 100 से 120 रुपए प्रति पौया के हिसाब से बेची जाती है।आबकारी विभाग व स्थानीय पुलिस इन ठेकों की कभी-कभी चेकिंग कर इतिभी कर लेती है। यहां ज्यादा सख्ती होने पर लोग सीमावर्ती जिले हरदोई व उनाव के सीमावर्ती ठेकों से शराब खरीद कर महंगे दामों पर बेचते हैं।आबकारी विभाग की टीम वही छापा डालती है। जहां पर इनकी सेटिंग नही होती है। एक आध को पकड़ कर वाहवाही लूटती है।राजधानी के इन इलाकों में अवैध शराब बनाने का धंधा लम्बे समय से चल रहा है।जिम्मेदारो से जब इसके बारे में पूँछा जाता है तो कोई माकूल जबाब नही मिलता है।सूत्रों का दावा है कि हकीकत को जानने के बाद भी आबकारी विभाग के बड़े अफसर मौन है।

बलिया में थानाध्यक्ष को पांच मीटर तक घसीटा

लखनऊ। बलिया कस्बे में लक्ष्मी पूजन के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। मुस्लिम बस्ती में बज रहे तेज आवाज वाले डीजे की शिकायत पर पर पहुंचे थानाध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी डीजे ट्राली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्राली के बीच फंस जाने से लगभग पांच मीटर तक घिसटते चले गए। जब तक वाहन रुका, तब तक उनकी गरदन की हंसुली यानि कालर बोन तथा दो से तीन पसलियां टूट गईं। पुलिस विभाग में खलबली मच गई। घायल थानाध्यक्ष को उपचार के लिए पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा ले जाया गया। वहां हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर किया गया। स्थिति गंभीर देख बेहतर उपचार के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया। घटना के बाद मौके से दो डीजे ट्रालियों को जब्त कर लिया गया है।जानकारी के अनुसार लक्ष्मी पूजन के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। अधिकांश जुलूस समाप्त हो चुका था, किंतु दो मूर्तियां लेकर जा रहे वाहन पर तेज आवाज में डीजे बजाजा जा रहा था। डीजे की तेज आवाज और नाच-गाने से परेशान बस्ती के लोगों ने थानाध्यक्ष को फोन कर शिकायत की। थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और युवाओं को डीजे बंद करने तथा वाहन आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।इसी बीच वह संकरे मार्ग के पास से दीवार से सट कर निकल रहे थे, तभी डीजे ट्राली अचानक चल पड़ी। थानाध्यक्ष दीवार और ट्राली के बीच फंस गए और आगे तक घिसटते चले गए। वाहन रोकने के लिए आवाज देने के बावजूद भी डीजे की आवाज के बीच वाहन नहीं रुका। जब युवाओं ने थानाध्यक्ष को फंसे हुए देखा तो बाहर निकाला। मूलरूप से आंबेडकरनगर के रहने वाले थानाध्यक्ष अजय की तैनाती डेढ़ माह पहले सितंबर में ही हुई थी।सीओ रसड़ा आलोक कुमार गुप्ता ने कहा कि डीजे ट्रालियों को जब्त किया गया है। संबंधित वाहन चालकों व आयोजकों के खिलाफविधिक कार्रवाई की जाएगी। घायल थानाध्यक्ष को लखनऊ वेदांता में भर्ती कराया गया है। पूजा समितियों को पहले ही डीजे की सीमा और मानक ध्वनि स्तर का निर्देश दिया गया था। नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

संक्षिप्त

3 मंजिले मकान में लगी भीषण आग,गोदाम का छज्जा गिरा, 4 फायरकर्मी घायल

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अलीगंज में 3 मंजिले मकान में भीषण आग लग गई। मकान से सटे गोदाम में धू-धूकर सामान जल रहा है। दमकल की 8 टीमें मौके पर पहुंची। मकान के सभी मंजिलों से आग की बड़ी लपटें निकल रही हैं। मौके पर अफरा-तफरी मची हुई है। बताया जा रहा है कि अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं। किमी दूर से धुएं का गुबार दिख रहा है। जानकारी मिलते ही बीकेटी, इंदिरानगर समेत आसपास के दमकल स्टेशनों से गाड़ियां पहुंचीं हैं। रेस्क्यू के दौरान ही गोदाम का छज्जा गिर गया जिससे 4 फायरकर्मी घायल हो गए। इनमें से दो की हालत नाजुक है। घर में फंसे तीन लोगों को बचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड के पहुंचने पर कुछ फायरकर्मी आग बुझाने में लग गए। वहीं, कुछ ने आसपास के लोगों के सहयोग से घरों से गैस सिलेंडर बाहर निकलवाना शुरू कर दिया। रेस्क्यू के दौरान मकान का छज्जा गिरने से उसके नीचे आए 4 फायरकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इनमें से 2 की हालत नाजुक हैं जिन्हें अस्पताल भेजा जा रहा है।

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे लोग

लखनऊ, आज समाचार सेवा। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रोजाना अधिक संख्या में लोग सीएमओ और नगर निगम दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। 21 दिन बाद जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन पर सीएमओ से अनुमोदन जरूरी है। लेट आवेदन करने वाले लोग भटक रहे हैं। रेलवे से रिटायर हुए पवन कुमार की मृत्यु 30 अगस्त को हुई थी। अंतिम संस्कार व तेरहवीं समेत अन्य कार्यक्रम करने के बाद परिवारीजन जब करीब एक माह बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने नगर निगम जोन छह कार्यालय पहुंचे तो वहां के कर्मचारी ने उन्हें नए नियम का हवाला दिया। प्रमाण पत्र बनवाने से पहले अनुमोदन के लिए सीएमओ कार्यालय भेज दिया। उनका बेटा अजीत सिंह सीएमओ कार्यालय पहुंचा तो वहां के कर्मचारी ने उन्हें बाद में आने की बात कहते हुए टरका दिया। अजीत ने बताया कि सीएमओ कार्यालय से अनुमोदन न मिल पाने की वजह से मां की पेंशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। नए नियम के तहत जन्म व मृत्यु पंजीकरण 21 दिन तक नगर निगम को करने का अधिकार है। इसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुमोदन सीएमओ से लेना पड़ता है। उसके बाद ही नगर निगम प्रमाण पत्र जारी करता है। सीएमओ कार्यालय में करीब तीन माह पुराने आवेदन अटके पड़े हैं। लोग नगर निगम और सीएमओ कार्यालय के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं। सीएमओ डॉ एनबी सिंह का कहना है कि लंबित मृत्यु प्रमाण पत्र का अनुमोदन दिलाकर उसका निस्तारण कराया जा रहा है। यदि किसी का अनुमोदन होने में देरी लग रही है तो उसकी जांच करवाई जाएगी।

फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या

लखनऊ। राजधानी के गुड़म्बा थाना क्षेत्र में एक सत्ताइस वर्षीय युवक नें फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस नें शव को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेजा है। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को डायल 112 नें थाना गुड़म्बा को बताया कि सत्यवान उर्फ सत्यम पुत्र राम विजय निवासी मायापुरी कालोनी निकट बालाजी स्वीटस थाना गुडम्बा जिनका मूल पता ग्राम नन्हेका पुरवा पोस्ट पंडित का पुरवा थाना थानगांव जिला सीतापुर है। इनकी उम्र 27 वर्ष है। इन्होने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।इस पर थाना स्थानीय पुलिस बल नें मौके पर पहुचकर जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि सत्यवान उर्फ सत्यम पुत्र राम विजय निवासी मायापुरी कालोनी निकट बालाजी स्वीटस थाना गुडम्बा मूल पता ग्राम नन्हेका पुरवा पोस्ट पंडित का पुरवा थाना थानगांव जिला सीतापुर अपने किराये के मकान मायापुरी कालोनी निकट बालाजी स्वीटस थाना गुडम्बा में रहते थे। पंखा से दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।पुलिस नें बताया कि शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।पुलिस के बड़े अफसरों व फोरेसिंक टीम नें घटनास्थल का निरीक्षण किया।पुलिस का कहना है कि मौके पर कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।पुलिस का कहना है कि मृतक नें आत्महत्या क्यों की है। इस बात की जाँच की जा रही है।

परिवहन निगम के कामकाज की समीक्षा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल ने शुक्रवार को परिवहन निगम मुख्यालय का दौरा कर निगम के विभिन्न कार्यों और चल रही परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा किया जाए, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अर्चना अग्रवाल ने निगम मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने बसों की लोकेशन, ओवरस्पीड मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने एसओएस पैनिक बटन और कस्टमर केयर रूम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों को दी जा रही सेवाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अपर मुख्य सचिव ने पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर बन रहे आधुनिक बस स्टेशनों की प्रगति रिपोर्ट भी देखी। उन्होंने कहा कि ये बस स्टेशन यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा से कोई समझौता न हो। समीक्षा बैठक के दौरान अर्चना अग्रवाल ने परिवहन निगम द्वारा भविष्य में लागू की जाने वाली तकनीकी नवाचार योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रैकिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और यात्री सुरक्षा उपायों को और सशक्त बनाया जाएगा, जिससे संचालन अधिक पारदर्शी और यात्रियों के लिए सुरक्षित हो सके।

पहले आओ-पहले पाओ योजना में छूट अवधि बढ़ी

लखनऊ,आज समाचार सेवा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों का आंवटन कराने पर मिल रही छूट अवधि को एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। अब यह ऑफर 6 नवम्बर तक वैध रहेगा और फ्लैट लेने पर 1 से 2 लाख रूपये तक की सीधी छूट मिलेगी। इसके साथ ही पूर्व में दी जा रही सभी प्रकार की छूट भी प्रभावी रहेंगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रेडी टू मूव फ्लैट्स को पहले आओ-पहले पाओ योजना के तहत बेचा जा रहा है। इस बार फेस्टिव सीजन के उपलक्ष्य में 22 सितम्बर से 22 अक्टूबर तक फ्लैटों पर बम्पर डिस्काउंट ऑफर निकाला गया था। इसके अनुसार 20 लाख से 50 लाख रूपये कीमत के फ्लैटों का पंजीकरण व आवंटन कराने पर 01 लाख की छूट, 50 लाख से 75 लाख रूपये कीमत के फ्लैटों पर डेढ़ लाख रूपये की छूट और 75 लाख रूपये से अधिक कीमत के फ्लैटों पर 02 लाख रूपये की छूट का प्रावधान किया गया था। उक्त अवधि को बढ़ा दिया गया है ।

सड़कों के गड्ढे भरने पर और 16 करोड़ खर्च होंगे

लखनऊ, आज समाचार सेवा। राजधानी की टूटी-फूटी सड़कों को अब राहत की उम्मीद जगी है। नगर निगम ने शहर की सड़कों के गड्ढे भरने के लिए 16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट स्वीकृत करने का प्रस्ताव तैयार किया है। शुक्रवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा की गई। कार्यकारिणी और सदन से मंजूरी की प्रत्याशा में यह रकम जारी कर दी जाएगी। नगर निगम पहले ही 10 करोड़ का बजट सड़कों के गड्ढे भरने पर खर्च कर चुका है। हालांकि इससे सभी गड्ढे नहीं भर पाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के सख्त निर्देश दिए थे। इसी के बाद नगर निगम हरकत में आया। महापौर सुषमा खर्कवाल ने अधिकारियों से विस्तृत प्रस्ताव मांगा और अब 16 करोड़ की नई राशि मंजूरी की तैयारी है। जल्द शुरू होगी मरम्मत महापौर ने बताया कि जैसे ही बजट को कार्यकारिणी और सदन से मंजूरी मिलती है, सड़कों की मरम्मत तेजी से शुरू कर दी जाएगी। नगर आयुक्त से कहा गया है कि वार्डवार प्राथमिकता तय की जाए और अधिक जर्जर सड़कों की मरम्मत पहले की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप लखनऊ की सड़कों को पूरी तरह गड्ढामुक्त बनाया जाएगा, अब किसी क्षेत्र में टूटी सड़कें नहीं दिखेंगी। नगर निगम ने तय किया है कि मरम्मत नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू कर दिसंबर तक पूरा कर ली जाए।

प्रयागराज में पत्रकार का हत्यारोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

लखनऊ। यूपी के प्रयागराज जिले के सिविल लाइंस एरिया में गुरूवार रात करीब साढ़े दस बजे स्थानीय पत्रकार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।घटना के बाद एक्टिव पुलिस टीमों ने शहर में छानबीन शुरू की।करीब दो घंटे बाद ही पत्रकार की हत्या में शामिल आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।एडिशनल सीपी कानून-व्यवस्था अजय पाल शर्मा ने बताया कि आरोपियों से 22 अक्टूबर को किसी बात को लेकर पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह की कहासुनी हुई थी। हत्या की वजह यही विवाद था।आरोपी ने 22 अक्टूबर को ही मछली बाजार से चाकू खरीदा और मौका देखकर हत्या कर दी।अजय पाल शर्मा ने बताया कि इस घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं।दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।हत्या के आरोपियों को बक्शा नहीं जाएगा।मृतक के परिवार को हर संभव जरूरी मदद भी की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पत्रकार एलएन सिंह (50) धूमनगंज थाना क्षेत्र के अल्कापुरी कॉलोनी में रहते थे।वह कई वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े थे। गुरूवार रात करीब 10.30 बजे सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के धरना स्थल के पास एलएन सिंह बैठे हुए थे।तभी दो युवक मौके पर चाकू लेकर पहुंचे और एलएन सिंह पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला बोल दिया।इसके बाद गंभीर रूप से घायल एलएन सिंह को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।पत्रकार एलएल सिंह हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह के भतीजे थे।हत्या के बाद काफी संख्या में वकील और पत्रकार मौके पर पहुंचे. पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और आरोपी को पकड़ने की रणनीति बनाई।सूचना के बाद पुलिस ने नेहरू पार्क, धूमनगंज में घेराबंदी की. बदमाशों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में आरोपी विशाल के दोनों पैरों में गोली लगी। उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

डॉ. शक्ति सिंह साधू (प्रधान सम्पादक), डॉ. प्रवीण (प्रबंध सम्पादक), एडवोकेट शैलेन्द्र श्रीवास्तव (कानूनी सलाहकार), राकेश अग्रवाल (जिला ब्यूरो उत्तर प्रदेश) अब्दुल नासिर स्टेट ब्यूरो उत्तर प्रदेश

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शक्ति सिंह द्वारा राज तरूण आफसेट, एल0जी0एफ0 5–14, अंसल सिटी सेंटर, हजरतगंज, लखनऊ– 226001 से मुद्रित तथा 486/238–डी, डालीगंज, निरालानगर, जनपद लखनऊ–226020 से प्रकाशित।

सम्पादक– शक्ति सिंह मो0 7052608007 नोटः समाचार पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।